CMYK

हिन्दी दैनिक

न्यूज गाइड

RNI No- UPHIN/2008/28258

आपका देश आपकी बात...

वर्षः 14, अंकः 38 पृष्ठ :8 www.newsguide.co.in E-mail : newsguidelko@gmail.com लखनऊ, शनिवार 26 नवम्बर, 2022 मूल्य 1.50

युवा विद्यार्थी नए भारत की नई तस्वीर बना रहे है : ओम बिरला

एजेंसी

रुड़की/नई दिल्ली। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को आईआईटी रुड़की के 175वें स्थापना दिवस को सम्बोधित किया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को बधाई

बिरला ने हर्ष व्यक्त किया की आईआईटी रुड़की के छात्रों ने विश्व पटल पर भारत का नाम रौशन किया है।

देते हुए बिरला ने कहा कि आईआईटी रुड़की से पढ़कर निकले हजारों विद्यार्थियों ने सम्पूर्ण विश्व में अपनी प्रतिभा के बल पर पहचान बनाई है तथा अपने ज्ञान और कौशल से देश में आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया है। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि युवा विद्यार्थी नए भारत की नयी तस्वीर बना रहे है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा की देश ने ठान लिया है कि भारत को

हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। बिरला ने हर्ष व्यक्त किया की आईआईटी रुड़की के छात्रों ने विश्व पटल पर भारत का नाम रौशन किया है। आईआईटी को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश का शीर्ष संस्थान बताते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु, पर्यावरण, मेडिकल, शिक्षा, संचार, सड़क से लेकर जीवन के कई क्षेत्रों में आईआईटी के अनुसंधान व आविष्कारों ने देश और समाज को नई दिशा दी है। चौथी औद्योगिक क्रांति का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा की डिजिटल युग और इंटरनेट क्रांति ने पूरे विश्व को बदल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल युग में देश का आम नागरिक अधिक सक्रियता से लोकतंत्र में भागीदार बन रहा है। भारत की प्राचीनतम लोकतान्त्रिक व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का लोकतंत्र एवं विविधता देश की शक्ति है । उन्होंने आगे कहा कि आज़ादी के अमृत काल में आईआईटी रुड़की ने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है । गत सात दशकों में देश द्वारा की गई प्रगति का जिक्र करते हुए बिरला ने कहा कि भारत के वैज्ञानिक, चिकित्सक, व्यवसायी और युवा पूरे विश्व में भारत की पहचान बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत की साख दुनिया में एक विश्वसनीय लोकतंत्र और उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने में भारत की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज वैश्विक स्तर पर भी भारत के युवा नेतृत्व कर रहे हैं और नवाचार, नई तकनीक, एवं शोध के क्षेत्र में विश्व की सबसे जटिल समस्याओं के निवारण में अपना योगदान के रहे हैं।

कबाड़ में बदले जाएंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहनः गडकरी

नागपुर, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा और इससे संबंधित नीति राज्यों को भेजी गई है। गडकरी ने यहां वार्षिक कृषि प्रदर्शनी एग्रो-विजन के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा, मैंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किये। इसके तहत भारत सरकार के सभी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा। मैंने भारत सरकार की इस नीति को सभी राज्यों को भेज दिया है। उन्हें भी राज्यों के स्तर पर इसे अपनाना चाहिए। गडकरी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल के दो संयंत्र लगभग शुरू हो गए हैं, जिनमें से एक प्रतिदिन एक लाख लीटर एथनॉल का उत्पादन करेगा, जबकि दूसरा संयंत्र चावल के भूसे का उपयोग करके प्रतिदिन 150 टन बायो-बिटुमेन का निर्माण करेगा।

हमीरपुर में दिल दहला देने वाली घटना...

3 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोच-नोच कर मार डाला

एजेंसी

हमीरपुर। स्थानीय नगर परिषद के वार्ड नंबर-8 में आवारा कुत्तों ने एक साल की मासूम बच्ची को नोच-नोच कर मार डाला। यह दिल दहलाने वाली घटना गतद्द दिवस शाम की बताई जा रही है, जब मासूम बच्ची शौच करने के लिए अपने ही घर के गयी तो उस पर आवारा कुत्ते टूट पड़े। बच्ची ने काफी शोर मचाया, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आवारा कुत्तों ने उस मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह परिवार जिला मुख्यालय में साफ सफाई का काम करता है और वह जिला होशियारपुर के भगत नगर का रहने वाला है। गौरतलब है कि उपमंडल भोरंज में भी पिछले दिनों आवारा कुत्ते लगभग कई बकरियों को अपना शिकार बना चुके हैं। यहां तक कि एक ही परिवार की 2 बकरियों को भी मार डाला था। जनता ने आरोप लगाया कि आवारा कुत्तों के बारे में पशुपालन विभाग से शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। विभाग केवल काम चलाऊ व अस्थाई कदम उठाकर ही आराम से बैठ जाता है। गौर हो कि इस घटना स्थल से उप-निदेशक पशुपालन विभाग का कार्यालय भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। फिर भी विभाग इन आवारा कुत्तों को अनदेखा करता रहा। इस दिल दहला देने वाली घटना से शहर में गहरा रोष व दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है । हमीरपुर थाना प्रभारी संजीव गौतम ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार मिन्हास ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे थे। यह बेहद ही दर्दनाक घटना थी। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिवार को अपनी तरफ से आर्थिक मदद दी है।

देश के 54 फीसदी ग्रामीण घरों में पहुंचा पानी : शेखावत

एजेंसी

जोधपुर। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में जल जीवन मिशन के तहत तेजी से काम हो रहा है। अब तक देश के 54 फीसदी ग्रामीण घरों में पानी पहुंचाया जा चुका है और वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जलस्त्रोतों का पुनर्भरण और जल संरक्षण बड़ी चुनौतियां है। युवा पीढ़ी को इस जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेना होगा। शुक्रवार को उन्नति विकास शिक्षण संगठन के तत्वावधान में माहेश्वरी समाज जन उपयोगी भवन में आयोजित वॉटर लीडर सम्मेलन में शेखावत ने कहा कि भारत जल को जगदीश मानने की परम्परा वाला देश है। मनुष्य के जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के उपरांत तक यदि कोई एक चीज निरंतर उसके साथ जुड़ी रहती

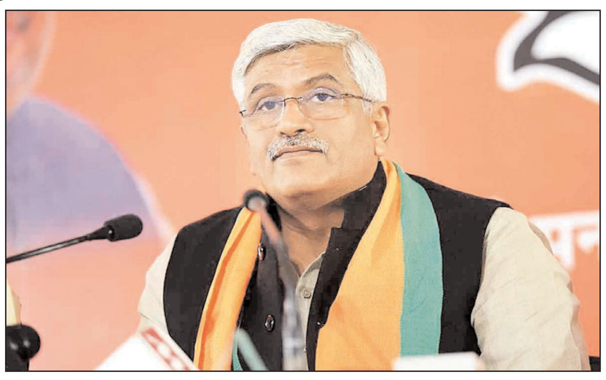

है तो वह जल है। जल स्वरूप किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जल जितने भी स्वरूप में है, चाहे वह नदी हो, तालाब या कुआं। सब एक-दूसरे से कहीं न कहीं एक चक्र के रूप में जुड़े हुए हैं। इनमें से एक भी कड़ी टूट जाती है तो परेशानी आती है। उन्होंने कहा कि जो आज हम जलवायु परिवर्तन के रूप में महसूस कर रहे हैं। जिन तालाबों के कारण यह भूजल वापस बढ़ सकता था। उन तालाबों की तरफ से भी हमारा ध्यान हट गया। समाज ने इन तालाबों की ओर देखना बंद कर दिया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि न तो हमारे तालाब बचे और न ही भूजल। चूंकि, यह संकट हमारी पीढ़ी ने खड़ा किया, इसलिए इससे निपटने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है।

उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को उच्चतम न्यायालय में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे और इस अवसर पर ई-न्यायालय परियोजना के तहत कई पहलों की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, जिसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री ई-न्यायालय परियोजना के तहत जिन पहलों की शुरुआत करेंगे, उनमें 'वर्चुअल जस्टिस क्लॉक', 'जस्टिस मोबाइल एप 2.0', डिजिटल अदालतें और 'एसथ्रीडब्ल्यूएएस' शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि ई-कोर्ट परियोजना कुशल और समयबद्ध, वादी केंद्रित, वहनीय, सुलभ, किफायती, पारदर्शी और जवाबदेह न्याय प्रणाली की परिकल्पना पर आधारित है। पीएमओ ने कहा कि यह परियोजना वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने का प्रयास है।

कांग्रेस ने हिंसा में शामिल अपराधियों का समर्थन किया, लेकिन भाजपा ने गुजरात में स्थायी शांति कायम की: शाह

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात में पहले असामाजिक तत्व हिंसा में लिप्त होते थे और कांग्रेस उनका समर्थन करती थी लेकिन 2002 में सबक सिखाने के बाद, अपराधियों ने ऐसी गतिविधियां बंद कर दीं और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य में स्थायी शांति कायम की। गुजरात में फरवरी, 2002 में गोधरा रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। शाह ने राज्य में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खेड़ा जिले के महुधा में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में एक रैली की।

उन्होंने आरोप लगाया, गुजरात में कांग्रेस के शासनकाल में (1995 से पहले), अक्सर साम्प्रदायिक दंगे होते थे। कांग्रेस विभिन्न समुदायों और जातियों के सदस्यों को एक-दूसरे के खिलाफ उकसाती थी। कांग्रेस ने ऐसे दंगों के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत किया और समाज के एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय किया।श्श शाह ने दावा किया कि गुजरात में 2002 में दंगे इसलिए हुए क्योंकि अपराधियों को लंबे समय तक कांग्रेस से समर्थन मिलने के कारण हिंसा में शामिल होने की आदत हो गई थी। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, ''लेकिन 2002 में सबक सिखाए जाने के बाद ऐसे तत्वों ने वह रास्ता (हिंसा का) छोड़ दिया। वे लोग 2002 से 2022 तक हिंसा से दूर रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफसख्त कार्रवाई कर गुजरात में स्थायी शांति कायम की है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के कारण इसके खिलाफ थी।

आनंद तेलतुंबडे को मिली जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे को मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह तेलतुंबडे को जमानत देने से संबंधित बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए 18 नवंबर को तेलतुंबडे की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी कि प्रथम दृष्टया तेलतुंबडे के खिलाफ एकमात्र मामला एक आतंकवादी समूह के साथ कथित संबंध और उसे दिए गए समर्थन से संबंधित है, जिसके लिए अधिकतम 10 साल जेल की सजा है। उच्च न्यायालय ने, हालांकि, एक सप्ताह के लिए अपने जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी, ताकि मामले की जांच कर रही एजेंसी एनआईए उच्चतम न्यायालय का रुख कर सके। तेलतुंबडे (73) इस मामले में गिरफ्तार कुल 16 आरोपियों में तीसरे आरोपी हैं, जिन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।

केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले 6 दिसंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले 6 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार की तरफ से 6 दिसंबर की सर्वदलीय बैठक के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सभी दलों को आमंत्रित किया है। बैठक के लिए संसद के दोनों सदनों-लोक सभा और राज्य सभा में सभी राजनीतिक दलों के संसदीय दल के नेता को आमंत्रित किया गया है। सर्वदलीय बैठक के लिए सभी दलों के लोक सभा एवं राज्य सभा संसदीय दल के नेताओं को आमंत्रित करते हुए लिखे पत्र में संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करने की अपील करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने उन्हें 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे होने वाली सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि इस सर्वदलीय बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान होने वाले विधायी कार्य और सत्र के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। सरकार की तरफ से बैठक में विधायी एजेंडे की जानकारी दी जाएगी वहीं विपक्षी दल भी अपने-अपने मुद्दों को बैठक में रखेगा जिन पर वो चर्चा कराना चाहेंगे। आपको बता दें कि, इस बार संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और इसके 29 दिसंबर तक चलने की संभावना है। सत्र के 23 दिनों के दौरान सदन की 17 बैठकें होंगी।

दिल्लीः चांदनी चौक के थोक बाजार में आग से 50 से अधिक दुकानें खाक

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तरी दिल्ली के चांदनी चौक में थोक बाजार भागीरथ पैलेस में भीषण आग लगने से 50 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम लगी इस आग पर काबू पा लिया गया है और अब वातावरण को ठंडा किया जा रहा है ताकि आग दोबारा न भड़क जाए घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दमकल विभाग के अनुसार, उन्हें आग लगने की सूचना बृहस्पतिवार रात नौ बजकर 19 मिनट पर मिली और दमकल की 40 गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया।

तांत्रिक की सलाह पर बच्चे की हत्या कर पीया खून, महिला समेत 3 को उम्रकैद

शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जिले में औलाद न होने पर तांत्रिक की सलाह पर एक बच्चे की हत्या कर उसका खून पीने वाली एक महिला समेत तीन आरोपियों को स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद शुक्ला ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने घटना का ब्योरा देते हुए बताया कि थाना रोजा के जम्मुका गांव में अपने मामा मुनेंद्र के यहां रह रही धन देवी के बच्चे नहीं हो रहे थे। किसी तांत्रिक की सलाह पर उसने पड़ोस में ही रहने वाले 10 वर्षीय लाल दास को टीवी देखने के बहाने अपने घर बुलाया तथा अपने दो साथियों सूरज तथा सुनील की मदद से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि इसके बाद तांत्रिक के बताए अनुसार धन देवी ने लाल दास को काटकर उसका खून पी लिया और मृतक के शव को घर के बाहर फेंक दिया। शुक्ला ने बताया कि छह दिसंबर, 2017 को मृतक के पिता ने रोजा थाने में मामला दर्ज कराया था और विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि इसी मामले में अपर सत्र न्यायालय तृतीय के न्यायाधीश एहसान हुसैन ने सभी पक्षों को सुनने के बाद धन देवी, सुनील तथा सूरत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक आरोपी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ में प्रबुद्धजन सम्मेलन को सम्बोधित किया

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत अलीगढ़ नये रूप में सामने है-योगी

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 'सबका साथ, सबका विकास' केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की हकीकत बना है। यह हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बना है। विभिन्न योजनाएं व्यक्तियों के स्वावलम्बन तथा सम्मान का प्रतीक बनी है। आज लोगों ने जातिवाद, क्षेत्र, मत तथा मजहब के आधार पर देश की सामाजिकता के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने वालों को दरकिनार करते हुए विकास को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर डबल इंजन की सरकार ने आपके सम्मान की रक्षा और सुरक्षा के लिए बेहतर माहौल देते हुए परिवर्तन का वाहक बनने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री आज जनपद अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने जनपद अलीगढ़ के विकास के लिए 86.55 करोड़ रुपये लागत की 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 16.48 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 70.07 करोड़ रुपये की 76 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय) के लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाभी, पी0एम0 स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को चेक प्रदान किये। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एम0वाई0 एस0वाई0) के लाभार्थियों को डेमो चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री जी ने बच्चों का अन्नप्राशन व स्वर्णप्राशन तथा गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की।

उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत 41 कूड़ा निस्तारण वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। अलीगढ़ के ताले, हार्डवेयर एवं विभिन्न प्रकार की मूर्तियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सम्मेलन में नगरीय सुविधाओं पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत साढ़े आठ वर्षों में आपने देश को बदलते हुए देखा है। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह देश के लिए गौरव की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव

- जनपद अलीगढ़ के विकास के लिए 86.55 करोड़ रु0 की लागत की 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास
- मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र तथा डेमो चेक व आवास की प्रतीकात्मक चाभी का वितरण किया

वर्ष में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। दुनिया के 20 बड़े देश, जिनका दुनिया के 80 फीसदी संसाधनों पर अधिकार है, वे जी-20 के नाम से जाने जाते हैं। भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले 01 वर्ष तक जी-20 के देशों की अध्यक्षता करेगा। यह भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है। विगत साढ़े आठ वर्षों में भारत में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को सभी ने नजदीक से अनुभव किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के साथ ही अलीगढ़ में भी विकास के कार्य किये गये हैं। अलीगढ़ में महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। यहां डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है, जिसके माध्यम से यहां के उद्यमियों को अपने हार्डवेयर के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत अलीगढ़ नये रूप में सामने है। यहां ट्रांसपोर्ट नगर भी स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद अलीगढ़ प्रदेश का प्रमुख जनपद और महानगर है। इसकी अपनी पहचान है। पौराणिक काल से लेकर देश की आजादी की लड़ाई के दौरान जनपद अलीगढ़ ने अग्रणी भूमिका में रहते हुए सदैव नेतृत्व प्रदान किया है। आजादी के बाद जनपद अलीगढ़ ने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने में अपनी भूमिका निभायी। बाबू जी श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में यहां के परम्परागत उद्यम को पुनर्जीवित करते हुए ताला नगरी के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। आज वे स्वयं यहां अलीगढ़ के हुनर को मंच प्रदान करने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत साढ़े आठ वर्षों में बदलते भारत को तथा पिछले साढ़े पांच वर्षों में बदलते उत्तर प्रदेश को आपने देखा है।

CMYK

हत्या के मामले में दंपती समेत पिता-पुत्र दोषी

कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई

उरई/जालौन, (यूएनएस)। जालौन में 9 साल पहले हुई दलित युवक की हत्या मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट में पति-पत्नी और पिता-पुत्र को दोषी करार दिया। सभी दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। आर्थिक दंड न देने पर सभी को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता रणकेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि मामला 2013 का है। 17 मार्च 2013 को रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम लिडऊपुर निवासी चौकीदार राकेश कुमार पुत्र गयादीन ने थाने में सूचना दी थी कि गांव के उत्तर पूर्व जंगल में गंदा नाला के पास एक अज्ञात युवक की लाश सड़ी-गली हालत में पड़ी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। जहां उन्होंने अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ हत्या तथा साक्ष्य छिपाने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया था। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक गीतम सिंह द्वारा की जा रही थी। इसी विवेचना के दौरान मृतक की शिनाख्त राजकुमार धोबी पुत्र मूलचंद निवासी शिवथाम थाना मिथिला जिला सीतापुर के रूप में हुई थी और यह शिनाख्त उसके भाई राकेश कुमार ने की थी। मृतक के भाई राकेश ने पुलिस को बताया था कि वह अपने भाई वीरेंद्र और राजकुमार के साथ गौतमबुद्धनगर जनपद के ग्राम करौली थाना सेक्टर

58 नोएडा किराए के मकान में रहकर एक प्राइवेट कंपनी ग्लोबल कंपनी एच-172 नोएडा में काम करते थे। राजकुमार के साथ कंपनी में रेखा भी काम करती थी। जो मोहल्ला 86 सेक्टर 63 नोएडा में रहती थी। इस दौरान राजकुमार का राखी के घर आना जाना था। घर पर आने जाने के कारण उसका पति रज्जन तिवारी राजकुमार के ऊपर शक करने लगा था और अंदरूनी रंजिश रखते हुए रास्ते से हटाने के लिए उसने दोस्ती बढ़ाते हुए पत्नी राखी के साथ मिलकर अपनी बहन की शादी में आमंत्रित किया था। साथ ही राजकुमार से 50 हजार रुपये शादी में खर्च के लिए उधार लिये थे, राखी और रज्जन ने पहले से ही राजकुमार की हत्या करने के इरादे से बुला लिया था और रज्जन ने अपनी पत्नी राखी, भाई राजू तिवारी व पिता जुग्गी पाल के सहयोग से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, साथ ही सिर काट कर सबूत मिटाने के लिए जंगल में फेंक दिया। जांच के दौरान जब सभी तथ्य निकलकर आए तो पति पत्नी और भाई व पिता के खिलाफ हत्या में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई। जिसके बाद 9 साल तक इस मामले की सुनवाई एससी-एसटी कोर्ट में चली। जहां विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट अत्याचार निवारण एक्ट के न्यायाधीश शिव कुमार द्वितीय ने साक्ष्यों के आधार पर रज्जन तिवारी, उसकी पत्नी राखी तिवारी, उसके भाई राजू तिवारी और पिता जुग्गीपाल को दोषी मानते हुए धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। साक्ष्य मिटाने के आरोप में भी आरोपियों को सश्रम 7 वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। वही अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी आरोपियों को सजा सुनाते हिरासत में ले लिया और उन्हें उरई जिला कारागार भेज दिया गया।

संक्षिप्त समाचार

डिप्टी सीएम केशव का अलीगढ़ कार्यक्रम रद्द

अलीगढ़, (यूएनएस)। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी शुक्रवार को अलीगढ़ में प्रबुद्धजनों के साथ सम्मेलन में भाग लेने और विकास योजनाओं की सौगातें देने अलीगढ़ पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दो कैबिनेट मंत्री भी अलीगढ़ आने वाले थे। हालांकि डिप्टी सीएम का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह अलीगढ़ आ रहे हैं। जो यहां पर भाजपा एमएलसी और जिलाध्यक्ष चौ. ऋषिपाल सिंह के बेटे की शादी समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन से जुड़ी बातचीत और संवाद करने वाले थे। इसके बाद वह विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम प्रस्तावित था। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना 7.40 बजे सर्किट पहुंचेंगे। यहां वह जनप्रतिनिधियों व पार्टी पदाधकारियों के मुलाकात करेंगे और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिसके बाद वह 8.30 बजे आईटीआई रोड स्थित बरौली विधायक ठा. जयवीर सिंह के घर जाएंगे। जिसके बाद वह रात 9 बजे जिलाध्यक्ष के बेटे की शादी में शामिल होंगे। जिसके बाद जिले से रवाना होंगे। प्रदेश के मापर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह शाम 6.30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद वह शाम 7 बजे रामघाट रोड तालानगरी स्थित होटल में पहुंचकर जिलाध्यक्ष व उनके परिवार से मुलाकात करेंगे और शादी समारोह में शामिल होंगे। जिसके बाद वह अलीगढ़ से रात 8 बजे रवाना हो जाएंगे।

आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी लागू होगी पुलिस आयुक्तालय प्रणाली

लखनऊ, (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जिलों में भी पुलिस आयुक्तालय (कमिश्नरेट) प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लोकभवन में मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज के संपूर्ण जिला क्षेत्र में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तीनों जिलों को पहले 'मेट्रोपोलिटन एरिया' घोषित किया जाएगा और उसके बाद इन क्षेत्रों में यह प्रणाली लागू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में पहले से लखनऊ, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), कानपुर नगर और वाराणसी में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू है। राज्य के 75 जिलों में अब सात जिलों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू हो जाएगी। जनवरी 2020 मे प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में यह व्यवस्था लागू हुई थी और इसके बाद मार्च 2021 में कानपुर नगर और वाराणसी में भी पुलिस आयुक्तालय प्रणाली की शुरुआत हुई।

लखनऊ में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, 39 नए मरीज आए चपेट में, अब तक 7 लोगों की मौत

लखनऊ, (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लोग लगातार डेंगू की चपेट में आ रहे है। अब तक डेंगू की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के चलते डेंगू से संक्रमित 39 नए मरीज सामने आए है। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, राजधानी में डेंगू से बिगड़े हालात नगर निगम की पोल खोल रहे है। डेंगू से बचाव के लिए यहां 80 फीसदी इलाकों में फागिंग ही नहीं की गई है। जिसकी वजह से जिले में डेंगू से हालात और बिगड़ रहे है। बता दें कि राजधानी में डेंगू से हालात बहुत खराब हो रहे है। डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं, डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम दावे कर रहा है, कि डेंगू से प्रभावित इलाकों में फॉगिंग की जा रही है। मगर, राजधानी में डेंगू बिगड़ते हुए हालात नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहे है। नगर निगम के दावों के बावजूद सिर्फ 20-25 प्रतिशत इलाकों में ही फागिंग की गाड़ियां पहुंच रही है। ऐसे में यहां पर डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या और बढ़ रही है। राजधानी लखनऊ में अब तक डेंगू से पीड़ित 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के चलते 39 नए मरीज सामने आए है। जिन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इनकी डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया जा रहा है। राजधानी में नगर निगम विभाग द्वारा दावा किया जा रहा था कि जिले में डेंगू से प्रभावित हर इलाके में फागिंग की जा रही है। मगर, जिले के 80 फीसदी इलाकों में फागिंग ही नहीं हुई है। नगर निगम केवल वीआईपी इलाकों में फागिंग कराकर ढिंढोरा पीट रहा है और कागजों पर ही फॉगिंग करने के आंकड़े है। लेकिन, राजधानी में 80 फीसदी इलाकों में फागिंग न होना, नगर निगम के हवाई दावों की पोल खोल रहा है।

पहले नहीं हुई कोर्ट मैरिज...दूसरी लड़की से मिला प्रस्ताव, फिर जान से मारने की धमकी

बांदा, (यूएनएस)। जिले के अतर्रा थाना क्षेत्र में राजस्थान के युवक को शादी का झांसा देकर एक लाख रुपये ठग लिए गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद समेत नौ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के अंगद का पुरवा निवासी समिश कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। उसमें बताया कि वह पिलानी झुंझुनू राजस्थान का निवासी है। उसने शादी के लिए बायोडाटा मैरिज ब्यूरो में डाला था। 10 दिन पहले फोनकर उसे शादी कराने का प्रस्ताव दिया गया। लड़की गरीब परिवार की बताकर शादी का पूरा खर्चा उसको उठाने की बात बताई गई। 12 नवंबर को बांदा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। रेलवे स्टेशन के पास एक लॉज में लड़की दिखाकर कोर्ट मैरिज के कागजात बनवाने के नाम पर 10 हजार रुपये ले लिए। अन्य कार्य के लिए मांगे गए रुपये नहीं देने पर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। इस पर विमलेश नाम के व्यक्ति ने दूसरी लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा। उसे तीन लड़कियां दिखाई गई। तब पांच अन्य लोग भी मौजूद थे। सभी के साथ वह अंगद का पुरवा पहुंचा। एक लड़की पसंद आने पर एक लाख रुपये ले लिए और कुछ दिन बाद शादी करने की बात कही। कुछ दिन बाद दिए गए नंबर पर संपर्क किया, तो जान से मारने की धमकी दी गई। अब नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। कोतवाली प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया पीड़ित समिश कुमार की तहरीर पर विमलेश वर्मा व तीन अज्ञात लड़कियों पांच अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

मजदूर का शव फंदा पर लटका मिला

बांदा, (यूएनएस)। मजदूर का शव कमरे में फंदा से लटका मिला। पिता ने पत्नी के मायके से नहीं आने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। बताया कि छह माह पहले शादी हुई थी। पत्नी को लेने गया तो ससुराल वालों ने मारपीट भी की थी। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के रमपुरवा गांव में हरिलाल (23) का शव शुक्रवार को सुबह कमरे में साफी के फंदे से लटका मिला। सुबह छोटे भाई सोमनाथ ने बुलाने के बाद भी जवाब नहीं मिलने पर अनहोनी की आशंका हुई। इस पर दरवाजा तोड़ा तब घटना पता चली। उसने पिता और मां को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव फंदे से उतार कर परिजन से पूछताछ के बाद पोस्टमार्टम कराया। पिता ने बताया कि हरिलाल चार भाइयों में दूसरे नंबर का था। केरल में मजदूरी करता था। वहां से 14 नवंबर को घर आया था। जून 2022 में हरिलाल की शादी जसपुरा थाना क्षेत्र के चंदवारा निवासी सुमन के साथ हुई थी। शादी के बाद अक्तूबर में बहू मायके चली गई। हरिलाल उसे लेने गया तो ससुराल वालों ने उससे मारपीट की थी। आरोप है कि पत्नी ने मां के कहने पर तीन माह का गर्भ भी गिरा दिया था। हरिलाल ने जसपुरा थाने में पत्नी व ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तब से बहू मायके से नहीं आई है। घटना के समय पिता निमंत्रण में गया था। घर में मां और छोटे भाई थे। थाना प्रभारी पंकज सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। अभी तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बबेरू में बनेगी बीएसएल-4 लैब, तीन सदस्यीय केन्द्रीय टीम ने लिए देखी जमीन, 100 बीघा में होगा निर्माण

बांदा, (यूएनएस)। बांदा के बबेरू में मरीजों की बेहतर जांच के लिए बीएसएल-4 लैब सिमौनी धाम में बनाई जानी है। इसके लिए जमीन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को अपनी तीन सदस्यीय टीम भेजा। टीम के सदस्य सुबह संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से बांदा आई और अपर सीएमओ से मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियनों के साथ सिमौनी धाम पहुंची। वहां पर प्रस्तावित 100 बीघा जमीन का जायजा लिया।गंभीर मरीजों को जांच के लिए महानगरों का चक्कर लगाना पड़ता है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के सिमौनीधाम में स्वामी अवधूत महाराज का हर वर्ष तीन दिवसीय विशाल मेला और भंडारे का आयोजन होता है। वहां पर केन्द्रीय मंत्रियों से लगाकर राज्य सरकार के मंत्री तक अवधूत नगरी में मत्था टेकने पहुंचते हैं। वहां पर बीएसएल-4 लैब बनवाए जाने के लिए स्वामी अवधूत महाराज ने प्रस्ताव रखा था। ताकि मरीजों को बेहतर इलाज और बेहतर जांच हो सके। यह प्रस्ताव काफी दिनों से पड़ा हुआ था। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को अपनी तीन सदस्यीय टीम भेजा। टीम के सदस्य सुबह संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से बांदा आई और अपर सीएमओ से मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियनों के साथ सिमौनी धाम पहुंची। वहां पर प्रस्तावित 100 बीघा जमीन का जायजा लिया। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को अपनी तीन सदस्यीय टीम भेजा। टीम के सदस्य सुबह संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से बांदा आई और अपर सीएमओ से मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियनों के साथ सिमौनी धाम पहुंची। वहां पर प्रस्तावित 100 बीघा जमीन का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव पर गौर किया और तीन सदस्यीय टीम महानिदेशक स्वास्थ्य भारत सरकार डा. अतुल गोयल, निदेशक एमसीजीसी डॉ. मीरा धुरिया, डॉ. अरविंद राय गुरुवार की सुबह संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से बांदा आए। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अजय कुमार से मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियनों के साथ सिमौनी धाम पहुंचे। वहां स्वामी अवधूत महाराज के साथ लैब बनाने के लिए प्रस्तावित 100 बीघा जमीन का निरीक्षण किया। टीम जमीन देखने के बाद वापस चली गई। अपर सीएमओ डॉ. अजय कुमार ने बताया कि टीम ने प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया है। इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क आदि व्यवस्था का जायजा लिया। यह रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी जाएगी। एसीएमओ ने यह भी बताया कि सभी बीमारियों की जांच इस लैब से होगी और यह देश की दूसरी लैब होगी। इस दौरान पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल, पूर्व विधायक चंद्रपाल कुशवाहा, लाखन सिंह, राजेश द्विवेदी, आनन्द स्वरूप द्विवेदी, कल्लू सिंह प्रधान, बच्चा सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

पीएम मोदी की यात्रा के बाद विश्वनाथ धाम में धन की बारिश

भक्तों की आमद हुई दोगुनी, दान के तोड़ दिए रिकॉर्ड

लखनऊ, (यूएनएस)। बाबा विश्वनाथ धाम में रिकॉर्ड चढ़ावा आया है। वित्तीय वर्ष में अभी तक यह चढ़ावा 28.37 करोड़ पहुंच गया है। बाबा विश्वनाथ के भक्त डिजिटल इंडिया मुहिम में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। चढ़ावे में से 40 फीसदी ऑनलाइन चढ़ावा आया है। कोरोना काल से ठीक पहले साल 2018-19 में सर्वाधिक 26.65 करोड़ रुपये चढ़ावा आया था। अप्रैल और मई में रिकॉर्ड 9.5 करोड़ रुपये चढ़ावा के तौर पर आए थे। काशी कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी आई है, जिसका सीधा प्रभाव बाबा विश्वनाथ के खजाने पर पड़ा है। काशी की देव दीपावली और श्रावण मास में श्रद्धालुओं की संख्या बीते वर्षों की तुलना में दोगुनी हो गई है।13 दिसंबर से जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, तबसे न केवल श्रद्धालुओं मंदिर में की संख्या बढ़ी है बल्कि सुविधाएं भी बढ़ा दी गई हैं। उद्घाटन के पहले मिलने वाले दान और बाद में लगभग दोगुना का अंतर पाया गया है। मंदिर का खर्चा और जिम्मेदारी भी बढ़ गई हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से न केवल दान बल्कि पूजन की गतिविधियां भी बढ़ी हैं। दान के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफार्म बनाकर दान लिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन टिकट और पूजा की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर में न केवल हुंडी दान बढ़ा है, बल्कि अन्य माध्यमों से भी दान में बढोत्तरी हुई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से पर्यटन उद्योग में उछाल आया है।इससे न केवल धार्मिक पर्यटन, बल्कि कॉर्पोरेट टूरिज्म में भी इजाफा हुआ है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया क्लोवर ऑर्गेनिक को सम्मानित

लखनऊ, (यूएनएस)। फसलों की जैविक खेती को अपनाने में 50 से अधिक एफपीसी की मदद करने, मिजोरम राज्य में 18 मीट्रिक टन जैविक अनानास और 350 मीट्रिक टन से अधिक जैविक अदरक की बिक्री का लक्ष्य प्राप्त करने वाली क्लोवर आर्गेनिक प्रा0लि0 को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह में क्लोवर द्वारा प्रवर्तित और एमओवीसीडीएनईआर के तहत समर्थित मिजोरम राज्य के ख्वाजोल जिले के तुईचांगरल एफपीसी को राज्य में सर्वश्रेष्ठ एफपीसी से सम्मानित किया गया। पुणे में आयोजित एक समारोह में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डव्टब्क्छम्त् के तहत कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता और दिये गये मूल्यवान योगदान के लिए क्लोवर ऑर्गेनिक को सम्मानित किया। भव्य समारोह में मिजोरम के ख्वाजोल जिले के तुइचांगराल एफपीसी को सीईओ वनलालरेमरुतपुइया को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सर्वश्रेष्ठ एफपीसी से सम्मानित किया गया। कंपनी ने हरियाणा के एक खरीदार द्वारा दिये गये 18 मीट्रिक टन रसायन मुक्त अनानास के ऑर्डर को पूरा करने के लिये उपरोक्त सभी एजेंसियों द्वारा निर्देशित और समर्थित एक समूह के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया था। क्लोवर ऑर्गेनिक के लिए पुरस्कार सीईओ संजय अग्रवाल ने प्राप्त किया। इस विशिष्ट उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद सीईओ संजय अग्रवाल ने इसका श्रेय किसानों की कड़ी मेहनत और कंपनी और अन्य सभी सक्षम एजेंसियों में जैविक प्रक्रिया में उनके द्वारा किए गए भरोसे को दिया। संजय अग्रवाल ने बताया की क्लोवर ऑर्गेनिक प्रा0 लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2008 में किसानों को अपनी फसलों की बिक्री के माध्यम से अधिकतम आर्थिक लाभ प्रदान करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए की गयी थी। क्लोवर ऑर्गेनिक ने किसानों के हित में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ साझेदारी की है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, किसान उत्पादक कंपनियों या किसान उत्पादक संगठनों जैसे राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश विविध कृषि सहायता परियोजना ष्न्च्क्ौच्ष्, 10,000 एफपीओ आदि का गठन और प्रचार जैसी योजनाओं के तहत क्लोवर ऑर्गेनिक खेती की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कई भारतीय राज्यों में किसानों की मदद कर रहा है। सीईओ संजय अग्रवाल ने बताया की 55 किसान उत्पादक कंपनियों और 40,000 से अधिक पंजीकृत किसानों के साथ 5 राज्यों, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कंपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। जैविक कृषि और जलीय कृषि उत्पाद निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी क्लोवर ऑर्गेनिक आंध्र प्रदेश में ख्याति हासिल कर रही है। दूरदराज के स्थानों, खराब सड़कों और रसद और परिवहन मुद्दों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए कंपनी ने बड़े लक्ष्य हासिल किये हैं। क्लोवर ऑर्गेनिक किसान हित को सदैव ध्यान में रखने, उत्पाद मूल्य श्रृंखला में समृद्धि सुनिश्चित कर किसानों के सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सारेगामा ने प्री लोडेड गानों के साथ कारवां मोबाइल लॉन्च किया

न्यूज गाइड। संवाददाता

लखनऊ। कारवां के साथ विभिन्न उद्योग मानदंडों को तोड़ने के बाद, सारेगामा ने कारवां मोबाइल लॉन्च किया है। भारत के कीपैड फोन बाजार में कारवां मोबाइल अब तक का पहला कीपैड मोबाइल है। जिसमें प्री-लोडेड गाने, शक्तिशाली स्पीकर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, डुअल सिम, एफएम, शक्तिशाली एलईडी टॉर्च और कई अन्य विशेषताएं हैं। जिस तरह कारवां ने प्री-लोडेड गानों के साथ अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक लीन-बैक सुनने का अनुभव बहाल किया, उसी तरह कारवां मोबाइल का लक्ष्य चलते-फिरते भी ऐसा ही करना है। यह उन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक मोबाइल है जो अभी भी कीपैड फोन के अनुभव की कसम खाते हैं। प्री-लोडेड गानों को लता मंगेशकर, आशा भोंसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और कई अन्य दिग्गज कलाकारों, मूड जैसे खुश, उदास आदि के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं द्वारा गीतों का सहज और परेशानी मुक्त चयन किया जा सके। प्री-लोडेड गानों को चलाने के लिए किसी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है और सुनने के अनुभव को बाधित करने के लिए कोई विज्ञापन ब्रेक नहीं होता है। 1500 प्री-लोडेड हिंदी गानों के

अलावा, फोन वायरलेस एफएम, डिजिटल कैमरा, एलईडी टॉर्च, ऑक्स आउट, मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट, वॉयस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, डुअल सिम, 8 जीबी मेमोरी कार्ड के साथ 2 जीबी फ्री स्पेस जैसी सुविधाओं से भरपूर है। किसी भी व्यक्तिगत संगीत संग्रह, वीडियो या छवियों और कई अन्य सुविधाओं के लिए। लंबे समय तक चलने वाले टॉकटाइम के लिए फोन में बड़ी डिस्प्ले और 2500 एमएएच की बैटरी है। यह मीडियाटेक प्रोसेसर से भरा हुआ है जो फोन को एक सुपरफास्ट प्रोसेसिंग पावर और एक बेजोड़ उपयोगकर्ता अनुभव देता है।

प्रसूता के इलाज में लापरवाही, बीजेपी विधायक ने सीएम को लिखा पत्र

लखनऊ, (यूएनएस)। सीएचसी अधीक्षक कहते हैं कि अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध है तो प्रसूता को मिली

अब अस्पताल दे रहा सफाई

क्यो नहीं? इलाज के बजाय अन्यत्र भेजा क्यो गया? ऐसे सवाल लोगो के जेहन में हैं जो लाजिमी भी हैं। यूपी के भदोही में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहां सरकारी अस्पताल में प्रसूता की इलाज में लापरवाही बरतने और बाहर तय मेडिकल स्टोर से दवा मंगाए जाने का मामला पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से शिकायत के बाद प्रकाश में आया है। मामला जनपद भदोही के औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का है जहां प्रसव के लिए एक

प्रसूता स्वास्थ्य केन्द्र आई थी, प्रसूता के सीजर करने के लिए परिजनों को पहले चिकित्सक ने बाहर से चिन्हित मेडिकल स्टोर से दवा लाने के लिए कहा और जब परिजन किसी और मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर लाए तो डॉक्टरों ने नाराजगी दिखाते हुए प्रसूता का इलाज करने से मना कर दिया और प्रसूता को मंडलीय अस्पताल मिर्जापुर रेफर कर दिया। मामला गंभीर होने पर मंडलीय अस्पताल न जाकर प्रसूता के साथ लगी आशा कर्मी उसे एक निजी क्लीनिक ले गई जहां उसका ऑपरेशन से प्रसव हुआ और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। इसकी लिखित शिकायत पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से की है। शिकायती पत्र में भदोही जिलाधिकारी गौरांग राठी और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संतोष कुमार चक के भी ऊपर आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के बाबत आरोपों से घिरे औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से हटाए गए अधीक्षक समीर उपाध्याय ने सफाई देते हुए कहा है कि ऑपरेशन के समय फोन पर पता चला कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, वो शादी समारोह में गए है और चार पांच घंटे बाद आएंगे। इस लिहाज से प्रसूता के हाई ब्लड प्रेशर और कंडीशन देखते हुए उसे मंडलीय अस्पताल रेफर किया गया था।बाहरी मेडिकल स्टोर से दवा लाने का आरोप गलत है, विधायक झूट बोल रहे है, अपनी राजनीति चमका रहे है।सीएचसी अधीक्षक समीर उपाध्याय ने कहा कि अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध है, पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर द्वारा उपरोक्त प्रसूता की कहानी निराधार है, प्रसूता के ऑपरेशन के लिए एक जरूरी दवा नही होने के चलते उसे मंडलीय अस्पताल मिर्जापुर रेफर कर दिया था।जब इस बाबत जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि आशाकर्मी और एएनएम के कहने पर प्रसूता का प्रसव हुआ। उस प्राइवेट अस्पताल का पंजीकरण नही था जिसे सील करने और लापरवाही बरतने वाली आशाकर्मी और एएनएम को निलंबित करने और स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को अन्यत्र जगह अटैच करने का आदेश दिया है।

लॉकडाउन में गई नौकरी तो गुलाब की खेती से महका घर

उरई/जालौन, (यूएनएस)। अहमदाबाद में महज 16 हजार रुपये महीने की नौकरी करने वाले युवक ने कुछ अलग करने की ठानीं तो सफलता भी मिल गई। लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद घर लौटे राहुल ने हताशा को अपने पास नहीं फटकने दिया। उन्होंने अपने खेत में गुलाब की खेती करने का मन बनाया और सफलता के पायदान पर चढ़ते हुए आज वह प्राइवेट नौकरी के लिए मोहताज नहीं रहे। गुलाब की खेती करके जीवन को खुशहाल बनाने के साथ औरों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। आटा थाना क्षेत्र का रिरुआ निवासी राहुल राजपूत ने 10 वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह नौकरी करने अहमदाबाद चले गए।यहां 16 हजार रुपये महीने की पगार पर नौकरी मिल भी गई। दो साल नौकरी करने के बाद कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते उन्हें घर लौटना पड़ा। इस दौरान घर पर बेगार बैठने से अच्छा उन्होंने अपने खेत में गुलाब की खेती तैयार करनी शुरू कर दी। राहुल ने बताया कि उन्होंने दो बीघा खेत में फूलों की खेती शुरू की। डेढ़ बीघा में गुलाब और आधा बीघा में गेंदा के पौधे लगाए। फसल तैयार होने पर कानपुर, औरैया सहित आसपास के जिलों में फूल बेचे। इस समय भी डेढ़ बीघा में गुलाब और आधा बीघा में गेंदा व अन्य फूलों की पौध तैयार की है। राहुल ने बताया कि डेढ़ बीघा खेत में हर रोज 50 किलो गुलाब निकल रहा है। जब सहालग और त्योहार में खासी मांग रहती है। अभी 50 रुपये किलो का गुलाब बिक रहा था। अभी भाव और चढ़ेगा। उन्होंने बताया कि अभी तक परंपरागत खेती की जा रही थी, उन्होंने थोड़ा बदलाव किया तो आमदनी भी बढ़ने लगी है। बताया कि 50 हजार रुपये की लागत से शुरुआत की थी। अब तक फूलों की बिक्री से लाखों रुपये की आमदनी हो चुकी है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। ग्रामीण परिवेश में जब राहुल ने फूलों की खेती शुरू की तो गांव व आस-पास के लोगों ने इसे नुकसान का सौदा बताया। लेकिन उन्होंने किसी की बात न मानकर गुलाब की खेती की। जब मुनाफा होने लगा तो आसपास के लोग भी अब उनसे गुलाब की खेती के बारे में जानकारी लेने आते हैं। बताया कि सबसे अधिक युवा उनसे फूलों की खेती के बारे में जानकारी लेने आते हैं।

संक्षिप्त समाचार

महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव पर परिचर्चा का आयोजन

लखनऊ, (यूएनएस)। सरल केयर फाउंडेशन द्वारा यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन (लखनऊ मंडल) के सहयोग से 25 नवम्बर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अवसर पर यूपी प्रेस क्लब में 'महिला हिंसा का महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव' विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में इंटरनेशनल इमेज कंसल्टेंट निधि शर्मा, शिक्षाविद शर्मिला सिंह, यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण सिंह गहरवार, सरस केयर फाउंडेशन की अध्यक्ष रीता सिंह, रश्मि सिंह, रश्मि सिंह जाड़ौन, रुचि रस्तोगी, रीना अग्रवाल, डॉक्टर दीप्ति जैन भल्ला, दीप्ति अग्रवाल सहित कई लोगों ने हिस्सा लिया। रीता सिंह ने कहा 'महिलाओं के प्रति हिंसा, शोषण एंव उत्पीडन के बढती घटनाओं को रोकने के उन्मूलन हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ के द्वारा 25 नवम्बर का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं के प्रति हिंसा का महिलाओं के जीवन के सर्वांगीण विकास पर गहरा शारीरिक और मानसिक प्रभाव पडता है। महिलाओं के प्रति हिंसा में जीवन साथी के द्वारा हिंसा, यौन हिंसा और उत्पीडन, मानव तस्करी, बाल विवाह और हत्या जैसी घटनाएं आती है। सामाजिक जागरूकता, कानून और पुलिस की मदद से इसको कम किया जा सकता है। कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए हस्ताक्षर संदेश भी लिखा गया।

महिला कारागार में कैदियों को वितरित किये कम्बल

लखनऊ, (यूएनएस)। आल इंडिया पयामे इंसानियत फेरम लखनऊ के तत्वाधान में महिला कारागार लखनऊ में स्थित महिला बंदियों को फेरम के द्वारा कंबल वितरित किए गए ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फेरम एक अराजनैतिक संस्था है जो गरीबों असहायो को समय-समय पर मदद करती है इस अवसर पर आर के सिह जेलर, एवं नारी बंदी निकेतन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे कंबल वितरण करते हुए ऑल इंडिया पयामे इंसानियत के पदाधिकारी मोहम्मद शफ़ीक चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा हमारी संस्था के द्वारा महिला एवं पुरुष जिलों में जा जाकर ऐसे कैदी जिनके ऊपर जुर्माना होता है वह जुर्माना अदा नहीं कर पाते हैं ऐसे कैदियों को संस्था की तरफ से उनका जुर्माना अदा करना तथा महिला एवं पुरुष जेलों में जा जाकर ऑल इंडिया पयामे इंसानियत की तरफ से हर संभव मदद की जाती है यह पुनीत कार्य है समाज के हर तबके एवं प्रबुद्ध जनों को आकर इसमें सहयोग करना चाहिए समाज को जोड़ने के लिए ऑल इंडिया में इंसानियत की तरफ से मेडिकल कैंप कंबल वितरण बाढ़ पीड़ितों की सहायता एवं सामाजिक सेमिनार आयोजित किए जाते हैं कंबल वितरण के समय लखनऊ स्थित नदवा कॉलेज के स्टूडेंट एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

पराली जलते पाए जाने पर क्षेत्रीय लेखपाल होंगे जिम्मेदार- जिलाधिकारी

कानपुर देहात, (यूएनएस)। जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का किसानों द्वारा पराली ना जलाने हेतु भ्रमण कर किसानों को जागरूक किया गया। जनपद के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के मित्रसेनपुर कंहिजरी में जल रही पराली को उनकी देखरेख में बुझाया गया।इस पर उन्होंने उपस्थित एसडीएम और लेखपाल को निर्देशित किया कि जिस किसान द्वारा पराली जलाई गई है उसके खिलाफ जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई करें।उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भ्रमण कर ग्रामीण जनों को पराली न जलाने हेतु डुग्गी मुनादि आदि के माध्यम से जागरूक करें। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत देते हुए लेखपाल को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर पराली न जलाने हेतु किसानों को जागरूक करें। अगर कहीं भी पराली जलती पाई जाएगी तो संबंधित लेखपाल की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही निलंबन की कार्यवाही भी की जाएगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुनीति द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर किसानों द्वारा पराली को जलाने से रोके तथा किसानो को पराली न जलाने हेतु जागरूक करें।

हवाई पट्टी व इटैली तथा मघई झील का निरीक्षण कर डीएम व एसपी ने दिए निर्देश

कानपुर देहात, (यूएनएस)। जिलाधिकारी नेहा जैन व पुलिस अधीक्षक सुनीति ने मरहमताबाद हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टूटी बाउंड्रीवॉल व उससे निकल रहे ग्रामीणों की जानकारी एसडीएम से लेकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस को हवाई पट्टी पर बेवजह वाहनों को आने से रोकने के लिए निर्देशित किया। ने इटैली झील व मघई झील का निरीक्षण किया। मघई झील की देखरेख कर रहे लोगों ने अमृत सरोवर तालाब बनाए जाने की मांग की। जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने इंदिरा गांधी वन चेतना एवं मनोरंजन केंद्र औनहा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएफ्ओ द्वारा संचालित नर्सरी का निरीक्षण कर सौन्दरीकरण कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।इसके पश्चात उन्होंने रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत इटैली झील का निरीक्षण कर डीएफ्ओ को निर्देशित किया कि झील के सौन्दरीकरण हेतु उचित कार्यवाही करें एवं जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें।इस दौरान एसडीएम महेंद्र सिंह व जितेंद्र कुमार, सीओ आशा पाल सिंह, डीएफ्ओ अनिल कुमार द्विवेदी, कोतवाल राजेश कुमार सिंह, एसआई देवेंद्र सिंह लेखपाल धर्मेंद्र तिवारी आदि लोग मौजूद रहे।

लाइसेंस विहीन संचालित मेडिकल स्टोर सीज

कानपुर देहात, (यूएनएस)। जनपद में आम जनमानस को जल्द स्वास्थ्य लाभ की दिशा में उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवा दिलाए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपद की औषधि निरीक्षक रेखा सचान द्वारा मेडिकल स्टोरों के कागजात व वहां बेची जा रही दवाइयों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक रेखा सचान द्वारा तहसील भोगनीपुर के ग्राम सट्टी में बिना वैध लाइसेंस के संचालित मंसूरी मेडिकल स्टोर की जांच थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान करीब ӗ50,000 की अंग्रेजी दवाइयां मौके पर बिक्री हेतु पाई गई।जिनको औषधि एवम प्रसाशन सामग्री अधिनियम की धारा 18ӗ27 के अंतर्गत फॉर्म 16 पर अंकित कर सीज किया गया। साथ ही एक संदिग्ध औषधि का जांच हेतु नमूना संग्रहित किया गया। उन्होंने पत्र को अवगत कराया कि विस्तृत विवेचना के उपरांत माननीय न्यायालय में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 18ӗ27 के अंतर्गत वाद दायर किया जाएगा।

सूचना विभाग ने भ्रामक अफ्वाह का किया खंडन

बलरामपुर, (यूएनएस)। सूचना विभाग बलरामपुर में सूचना जारी करते हुए बताया है कि जनपद में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफ्वाह फैल रही है कि जनपद में एक बांध है जो जर्जर कभी भी टूट सकता है एवं बाढ़ की स्थिति आ सकती है।वही इस को ध्यान में रखते हुए सूचना विभाग बलरामपुर द्वारा सूचना जारी कर बताया गया है की यह खबर बिल्कुल भ्रामक एवं असत्य है ऐसी कोई घटना जनपद में नहीं होने वाली है जिससे कोई परेशानी नहीं है और लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ऐसी भ्रामक चीजों पर ध्यान ना दें,बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया है आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहेगा तथा बारिश इत्यादि की कोई संभावना नहीं है।कृषक भाई अपनी फ्सल की बुवाई बिना किसी भय के करें। सोशल मीडिया पर किसी भी अफ्वाह को प्रसारित करने से बचें।और इस पर बिल्कुल ही ध्यान ना दें और किसी प्रकार की कोई ब्राह्मण चीजों का खुद भी प्रचार-प्रसार ना करें।

पत्रकार के पिता के निधन पर जिलाधिकारी ने जताया शोक

औरैया, (यूएनएस)। जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं भारत विकास परिषद सहित अन्य संगठनों से जुड़े मनोज दुबे निवासी फ्फ़्रूंद रोड दुर्गा नगर दिबियापुर के 73 वर्षीय पिता मूल चंद्र दुबे के निधन पर जनपद के जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह सहित जनपद के कईसमाजसेवी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, अधिवक्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर शोक जताया और परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया।इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी राघव मिश्रा,सभासद राहुल दीक्षित,कमलेश अवस्थी,धर्मेंद्र गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठजन उपस्थित रहे।

लिंग आधारित हिंसा को ख़त्म कर के ही देश का विकास संभव है

न्यूज गाइड, सवांददाता

वाराणसी। 16 दिवसीय महिला हिंसा विरोधी पखवाडे की शुरुआत 25 नवम्बर को भारतीय शिक्षा निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुबारकपुर, बेनीपुर वाराणसी में दोपहर 12 बजे से अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े के शुभारंभ पर सभा का आयोजन किया गया। पूरी दुनिया में 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक 16 दिवसीय महिला हिंसा विरोधी पखवाडा मनाया जाता है 7 उसी कड़ी में ग्रामीण पुनर्निर्माण संसथान, आजमगढ़ और एशियन ब्रिज इंडिया, वाराणसी द्वारा संयुक्त रूप साधिका संस्था के सहयोग से 16 दिवसीय महिला हिंसा विरोधी पखवाडा की शुरुआत 25 नवम्बर 2022 को भारतीय शिक्षा निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुबारकपुर, बेनीपुर वाराणसी में दोपहर 12 बजे से अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन और जेंडर वाल बुक के अनावरण कर के किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों का स्वागत विद्यालय के अध्यापक रहमान जी ने करते हुए अतिथियों को पुष्पगुछ और माल्यार्पण कर किया। आज के कार्यक्रम का विषय प्रवेश एशियन ब्रिज इंडिया के अध्यक्ष श्री मोहम्मद मूसा आज़मी के द्वारा किया गया और जेंडर वाल बुक के बारे में बताते हुए कहा की जब तक भारत के प्रत्येक विद्यालय में इस तरह की जेंडर वाल बुक की स्थापना नहीं होगी ।और बच्चो को बचपन से ही जेंडर यानि लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव के प्रति जागरूक और संवेदनशील नहीं किया जायेगा तब तक एक महिला हिंसा मुक्त विकसित भारत का सपना कभी पूरा नहीं होगा और ऐसे में भारतीय शिक्षा निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुबारकपुर, बेनीपुर ने जिस तरह की पहल की है यह अपने आप में एक नयी परंपरा को जन्म देगा और भारत को एक लिंग आधारित महिला हिंसा मुक्त राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर जेंडर वाल बुक का अनावरण करते हुए मुख्यअतिथि प्रो संजय, समाज कार्य विभाग, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने कहा की ÷जब तक समाज में महिला हिंसा होती रहेगी और लिंग के आधार पर महिलओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता रहेगा तब तक देश का सम्पूर्ण विकास संभव नहीं है, महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों को पाने के लिए हम पुरुषों लड़कों को आगे आना होगा घर के काम से लेकर अधिकारों को पाने की लड़ाई तक हर कदम में साथ देना होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है की भारत के हर व्यक्ति को समझना होगा के लिंग आधारित हिंसा क्या होती है और उसको रोकने में उनकी क्या भूमिका होगी तभी हम सही मायने में एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते है। इस अवसर पर दख़ल संगठन से आई मैत्री जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि एक महिला के साथ हिंसा पैदा होने से ही शुरू हो जाती है और निरन्तर जारी रहती है घर में होने वाली हिंसा को हम हिंसा मानने को तैयार नहीं होते परंतु लिंग आधारित हिंसा घर परिवार में ही सबसे ज्यादा होती है। विनोद कुमार कस्तूरबा सेवा समिति, संजू देवी प्रधान गणेशपुर, मीरा उदय सेवा संस्थान, ने अपने विचार रखे और समाज में महिलाओं तथा लड़कियों के प्रति बढती हिंसा पर चिंता व्यक्त की। सब इंस्पेक्टर महिला थाना प्रभारी श्रीमती अंजू यादव ने कहा कि उनके थाने में आने वाली अधिकतर घटनाएं घरेलू हिंसा की होती हैं और उसको रोकने एवं कम करने के लिए यह आवश्यक है कि हम बचपन से ही घरों में लड़को को विशेष रूप से एक संवेदन्शील व्यक्ति के रूप में तैयार करे और अपने घरों में गैर बराबरी को खतम करने का प्रयास करे। इस कार्यक्रम में 600 बच्चों और उनके परिवार के लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सरीता फील्ड फैसिलिटेटर, दीपक, विजय, जगदीश और करन कम्युनिटी मोबिलैज़र, धीरज, पंकज, और शबनम समाज कार्य विभाग महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थीयों अपना महत्वपूर्ण समय और योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन दीक्षा पांडे म.गा.का. विद्यापीठ ने किया और भारतीय शिक्षा निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुबारकपुर, बेनीपुर के प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता वर्मा धन्यवाद ज्ञापन किया।

मैनपुरी उपचुनावः सपा और भाजपा के बीच होगा दिलचस्प मुकाबला

केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का सपा पर तंज

पूरा खानदान वोट मांगने उतर आया हैः बघेल

लखनऊ, (यूएनएस)। 25 नवम्बर। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव बहुत अहम हो गया है। ये सीट अब तक समाजवादी पार्टी का अभेद्य दुर्ग मानी जाती रही रही है। इस के चुनाव प्रचार में सपा का कुनबा एकजुट हो गया है। बीजेपी इस सीट पर जीत खातिर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुलायम सिंह यादव के शिष्य और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सपा पर तंज कसा हैं। उन्होंने कहा कि पूरा खानदान वोट मांगने उतर आया है। जो समाजवादी पार्टी केवल नॉमिनेशन कर चली जाती थी और केवल जीत का सर्टिफिक्रेट लेने आती थी। आज प्रधानी की तरह घर-घर सातों लोग वोट मांग रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि वो हताश और निराश हैं। उन्होंने शिवपाल सिंह यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन पर ये कहावत लागू होती है कि हमें कोई और नहीं तुम्हें कोई ठौर नहीं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं रहता है। मकान, दुकान सुरक्षित नहीं रहते है। नौकरियों में सूची दी जाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड़ में रहती है। जो फौजे शांति काल में पसीना बहा लेती है। उन्हें खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। बीजेपी की चुनावी रणनीति है कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लोगों को याद करना है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। सपा की तरफ से डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य से चुनावी टक्कर है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर मुकाबाला दिलचस्प हो गया है। सपा अपने गढ़ और नेताजी की परम्परागत संसदीय सीट किसी भी हालत में खाते से बाहर नही देने खातिर दिनरात एक किये हुए है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रायः उपचुनाव में मीटिंगे नही लगाते रहे हैं किंतु आज उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है मैनपुरी का उपचुनाव तो सैफ़ई में डेरा डाल दिये हैं और बराबर मैनपुरी में दौड़ रहे हैं। उधर बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा रखी है। मंत्री, विधायक, सांसद और बीजेपी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारे ओहदेदार मैनपुरी की सड़कें नाप रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी जुटे हैं। अब मैनपुरी के मतदाताओं की मर्जी तो बाद मतदान ईवीएम खुलने र ही पता चलेगी। कुछ भी हो मैनपुरी का उपचुनाव मिशन 2024 की प्रस्तावना जरूर लिखने जा रहा है।

लोगों को जाम से नहीं मिल रही निजात, कई किलोमीटर लंबे जाम से जूझे राहगीर

कन्नौज, (यूएनएस)। छिबरामऊ में जाम की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल रही है। एक साल से जीटी रोड पर लगने वाले जाम लोगों को अब काफी परेशानी होने लगी है। कृषि उत्पादन मंडी समिति के पास कछुआ गति से हो रहा ओवरब्रिज का निर्माण जीटी रोड पर जाम की समस्या का प्रमुख कारण है। लगे जाम में घंटों रेंगने के बाद वाहन चालक और यात्री परेशान हो जाते हैं रोजाना आए दिन घंटों और कई किलोमीटर लगता लंबा जाम। नगर में नेशनल हाईवे 91 का 1 साल से धीमी गति से काम चल रहा है। जिससे अब शहर के लोगों और ग्रामीण से आने वाले किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। पूर्वी बाईपास, 100 शैया रोड, कांशीराम कालोनी, फर्रुखाबाद चौराहा, ताजपुर चौराहा, पश्चिमी बाईपास व कृषि उत्पादन मंडी समिति के आसपास जाम लगना तय है। वाहनों के संपर्क मार्गो की ओर रुख करते ही जाम लगना शुरू हो जाता है। सबसे गंभीर समस्या कृषि उत्पादन मंडी समिति के पास की है। इन दिनों सैकड़ों की संख्या में धान व मूंगफली की ट्रालियां पहुंच रही है। मंडी समिति के सामने एक लेन से ही आवागमन होने के कारण यहां पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। जबकि दिल्ली से पूर्वांचल की ओर जाने वाली रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले लोगों को घंटों जाम में फ्स कर परेशान होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या ट्रैफ्कि पुलिसकर्मियों की है। ट्रैफ्कि पुलिसकर्मी न होने की वजह से लोग आड़े तिरछे बाहर लगा देते हैं जिससे कई घंटों लंबा जाम लगा रहता है। एसडीम अशोक कुमार का कहना है कि कार्यदायी संस्था जीआर इंफ्रा के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं कोतवाल संतोष कुमार कुशवाहा ने कहा कि जाम से निजात के लिए चौराहों व मंडी समिति के पास पुलिस बल को तैनात किया जाएगा।

आज राजभवन घेरेंगे किसान, बिजली फ्री करने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन

लखनऊ, (यूएनएस)। नीतियों को लेकर किसान फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर चुके हैं। 26 नवंबर को प्रदेश केक किसान राजभवन का घेराव करेंगे। इससे पहले 19 नवंबर को किसान संगठन विजय दिवस मना चुके हैं। 19 नवंबर को ही सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया था। हालांकि उसके बाद सरकार ने जो किसानों से वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया। ऐसे में 26 नवंबर को हजारों किसान राजभवन का घेराव करेंगे। इससे पहले किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली में धरना दिया था। विजय दिवस में किसान संगठन गांवों में ढोल-नगाड़ों, बैंड-बाजों और किसानी आंदोलन के गीतों के साथ जश्न और विजय मार्च निकाले जाएंगे। रात्रि के समय दीपमालाओं-मोमबत्तियों, आतिशबाजी के साथ किसान कानून वापसी की जीत की खुशी जाहिर करेगा। इससे पहले किसान संगठनों ने लखनऊ में भी बैठक की थी। इसमें तय किया था कि आंदोलन का प्रचार- प्रसार चारों तरफ किया जाए। एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्जा माफी, किसान पेंशन, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी जैसी तमाम बाकी मांगों के लिए आंदोलन के दूसरे चरण का बिगुल बज चुका है। 26 नवंबर को देश भर में राजभवन मार्च की तैयारियां जोरो पर हैं। लखनऊ में भी ईको गार्डन में महापंचायत के बाद राजभवन मार्च की तैयारियां चल रही हैं। जिले से अधिकाधिक संख्या किसानों की भागीदारी के लिए भाकियू,किसान सभा, जय किसान आन्दोलन, क्रांतिकारी किसान यूनियन, भारतीय किसान श्रमिक जन शक्ति यूनियन आदि प्रमुख किसान संगठनों के राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिलास्तरीय पदाधिकारी गांव-गांव जनसंपर्क में जुटे है।

सड़क हादसे में 55 साल के व्यक्ति की मौत

झांसी, (यूएनएस)। गुरुवार को सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वह दर्जी के पास कपड़े उठाने के लिए बाइक से जा रहा था। रास्ते में अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मौत के बाद घर पर कोहराम मच गया। जनपद के पूंछ थानाक्षेत्र के चितगुवां गांव निवासी अब्दुल वहीद खां (55) पुत्र जगूर खा मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहे थे। परिजनों ने बताया कि अब्दुल वहीद ने खिल्ली गांव के दर्जी को कपड़े सिलवाने को दिए थे। गुरुवार सुबह वह घर से बाइक लेकर दर्जी के पास कपड़े उठाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वह घायल हो गए।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन के सम्बन्ध में सीडीओ ने वीसी के माध्यम से समीक्षा कर दिए निर्देश

कानपुर देहात, (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश शासन,विभागीय निर्देश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन के सम्बन्ध में जूम बैठक के द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारी से वार्ता की। उन्होंने प्रत्येक विकास खण्ड हेतु निर्धारित 60 वैवाहिक जोड़ों के सापेक्ष पंजीकृत जोड़ों की स्थिति के बारे में जानकारी चाही। अद्यतन स्थिति के अनुसार पंजीकृत जोड़ों की संख्या 151 है। उन्होंने समस्त बीडीओ को निर्देशित किया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पंजीकरण की कार्यवाही प्रत्येक दशा में ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य से वैवाहिक जोड़ों का पंजीकरण अधिक होने पर भी धनराशि आपको उपलब्ध करायी जाएगी।

उत्तर रेलवे

ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/सा0, मंडल रेल प्रबंधक, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

1.	ई–निविदा सूचना सं0	1074–वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता–उत्तर रेलवे–लखनऊ–द्वितीय कॉल दिनांक 24.11.2022
2.	कार्य का नाम	लखनऊ मंडल के अंतर्गत लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद (AYC) जौनपुर, भदोही रेलवे स्टेशनों पर प्रकाश सुविधाओं में सुधार हेतु विद्युत कार्य।
3.	अनुमानित लागत	रु. 93,30,035.74/– (तिरानवे लाख तीस हजार पैंतीस रुपये एवं चौहत्तर पैसा मात्र)
4.	ई–निविदा की कीमत	शून्य।
5.	बयाना राशि	रु. 1,86,600/– (एक लाख छियासी हजार छः सौ रुपये मात्र)
6.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	06 माह।
7.	ई–निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि व समय तथा खोलने की तिथि	दिनांक 23.12.2022 को 15:00 बजे तक तथा खुलने का समय उसी दिन 15:30 बजे वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/सा0, उत्तर रेलवे, हज़रतगंज, लखनऊ के कार्यालय में।
8.	प्रस्ताव की वैधता	ई–निविदा खुलने की तिथि से 60 दिन।
9.	उत्तर रेलवे की वेबसाइट	अतिरिक्त सूचना उत्तर रेलवे की वेबसाईट www.ireps.gov.in पर चेक की जा सकती है।
10.	योग्यता मानदण्ड	केवल वही निविदाकर्ता योग्य होंगे जो योग्यता मानदण्ड को पूरा करते हों।
10.a	तकनीकी योग्यता मानदण्ड	निविदाकर्ता के पास किसी भी राज्य सरकार द्वारा जारी फर्म के नाम से वैध विद्युत ठेकेदारी लाइसेन्स होना चाहिए तथा फर्म अपने ऑफर के साथ विद्युत लाइसेन्स के सभी विवरण संलग्न करें।
10.b	तकनीकी योग्यता मानदण्ड– Similar Nature of work	इस निविदा के लिए तकनीकी पात्रता मानदंड के निर्धारण के लिए केवल निम्नलिखित कार्य को समान कार्य माना जाएगा। निविदाकर्ता भौतिक रूप से निविदा खोलने की तारीख के पिछले 07 (सात) वित्तीय वर्षों और निविदा खुलने वाले माह से पिछले माह की अन्तिम तिथि तक के लिए यानी पात्रता अवधि में निम्नलिखित कार्य पूर्ण या पर्याप्त रूप से पूर्ण होने चाहिए। (i) तीन समान कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य का 30% के बराबर राशि से कम न हो, **अथवा** (ii) दो समान कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य का 40% के बराबर राशि से कम न हो, **अथवा** (iii) एक समान कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य का 60% के बराबर राशि से कम न हो
10.c	Definition of similar nature of work	इस निविदा हेतु तकनीकी योग्यता का निर्धारण केवल समान परवर्ती के निम्नलिखित कार्य मान्य होंगे। Wiring/Rewiring in building with associated electrical works. Or Lighting arrangement in buildings, circulating area, yard, street etc. with associated electrical works. Or Wiring/Rewiring, Lighting arrangement in buildings with associated electrical works.
10.d	वित्तीय योग्यता मानदण्ड	The tenderer must have minimum average annual contractual turnover of V/N or 'V' whichever is less; where V= Advertised value of the tender in crores of Rupees N= Number of years prescribed for completion of work for which bids have been invited. The average annual contractual turnover shall be calculated as an average of "total contractual payments" in the previous three financial years, as per the audited balance sheet. However, in case balance sheet of the previous year is yet to be prepared/ audited, the audited balance sheet of the fourth previous year shall be considered for calculating average annual contractual turnover. The tenderers shall submit requisite information as per Annexure-VIIB, along with copies of Audited Balance Sheets duly certified by the Chartered Accountant/ Certificate from Chartered Accountant duly supported by Audited Balance Sheet.

सूचना सं0– 1074–वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता–उत्तर रेलवे–लखनऊ–द्वितीय कॉल दिनांक : 24.11.2022 3150/22

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

क्रेडफोर्स की अंतरराष्ट्रीय जालसाजी ने तोड़ दिए 218 परिवारों के सपने कर दिया उन्हें लाचार

कंपनीं के संस्थापक निर्दोष निवेशकों की करोड़ों की रकम लेकर फरार

लखनऊ, (यूएनएस)। क्रेडफ ेर्स एशिया लिमिटेड की अंतर्राष्ट्रीय जालसाजी का शिकार हुए 218 भारतीय निवेशकों ने संयुक्त रूप से पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में। उन्हें न्याय दिलाने में मदद करने की गुहार लगाई है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन निवेशकों ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। इएं निवेशकों में से ज्यादातर उम्रदराज और रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई क्रेडफोर्स एशिया लिमिटेड में निवेश की थी। इन निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद थी लेकिन बदले में उन्हें मिला धोखा। इस आघात के चलते 6 निवेशक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित निवेशकों का पक्ष रखते हुए आदित्य बाजोरिया व तनवीर डगमैन ने बताया, क्रेडफोर्स एशिया लिमिटेड कंपनी नई दिल्ली में पंजीकृत है और इसे पहले टीसीजी हैमिल्टन के नाम से जाना जाता था और सीएफ्ओ और निदेशक राजीव गुप्ता और उनकी पत्नी गीतिका गुप्ता द्वारा प्रचारित किया जाता है जिसमें अन्य निदेशक संजीव शुक्ला और संजीव ढींगरा शामिल हैं। यह एक शिक्षा और क्रेडेंशियल कंपनी है। निवेशकों के अनुसार, दिसंबर 2019 तक, कंपनी ने निवेशकों को तरजीही शेयर जारी करके 70 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए थे, और 31 मार्च, 2018 तक, लगभग 250 करोड़ रुपये रिजर्व में रखे थे। हालांकि, 2017-18 से कंपनी ने कथित तौर पर आयकर रिटर्न जैसे वैधानिक अनुपालन को पूरा नहीं किया और निवेशकों को भुगतान करने में हीलाहवाली शुरू कर दी गई। कंपनी ने कोविड के चलते परिचालन कठिनाइयों का हवाला दिया और जल्द से जल्द राशि का भुगतान करने का वादा किया। करीब 218 निवेशक प्रभावित हुए और 55 करोड़ रुपये का निवेशकों का मूलधन कंपनी के पास फ्स गया। लखनऊ के रहने वाले राजीव गुप्ता और गीतिका गुप्ता, ने दिल्ली और गुड़गांव में आफ्सि के साथ क्रेडफोर्स एशिया लिमिटेड की स्थापना की। इन दोनों ने 218 निर्दोष निवेशक परिवारों को धोखा दिया, जिनमें से अधिकांश वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र हैं जिन्होंने अपनी जीवन भर की बचत इस जालसाजी के चलते गंवा दी। दुर्भाग्य से, छह निवेशकों की भी मृत्यु हो गई क्योंकि जालसाजों ने उनकी गाढ़ी कमाई के लिए उनके बार-बार किए गए अनुरोधों की अनदेखी की और उन्हें समय रहज उनके इलाज के लिए जरूरी पैसे भी नहीं मिल सके। इन जालसाजी के चलते मौत की मुंह मे जाने वाले निवेशकों में कुछ कैंसर पीड़ित भी थे। शेष निवेशक अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी खोने के बाद सदमे की स्थिति में हैं। इनमें से भी कुछ निवेशकों का स्वास्थ्य गम्भीर अवस्था में हैं और कैंसर जैसी गंभीर चिकित्सा स्थितियों से जूझ रहे हैं। निवेशकों के अनुसार लखनऊ के मूल निवासी एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र राजीव गुप्ता और एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर आसीन गीतिका गुप्ता द्वारा 12.25 प्रतिशत के निश्चित लाभांश के साथ प्रेफ्रेंशियल शेयरों के रूप में क्रेडफोर्स एशिया लिमिटेड में निवेश करने के लिए उन्हें धोखा दिया गया था। बाद में, दिसंबर 2019 से, उन्होंने कोविड का हवाला देते हुए मूलधन और लाभांश का भुगतान बंद कर दिया। निवेशकों ने बताया कि गुप्ता परिवार ने निवेशकों को धोखा देते हुए और बिना उनकी सहमति के एक नई कंपनी, एडवांटिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाकर निवेशकों को धोखा देना जारी रखा और क्रेडफोर्स एशिया लिमिटेड के शेयरधारकों को उनके कानूनी ऋणों का भुगतान किए बिना सभी संपत्तियों, कर्मियों, अनुबंधों और बौद्धिक संपदा को नई कंपनीं हस्तांतरित कर दिया। क्रेडफोर्स एशिया लिमिटेड के खाते में महज 4,000 रुपये होने के बाद भी, इन दोनों ने कुल 20 करोड़ रुपये की अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए पांच महीने बाद की तारीख डालते हुए क्रेडफोर्स निवेशकों के पोस्ट डेटेड चेक भी भेज दिए। जैसा कि अपेक्षित था, सभी चेक बाउंस हो गए और पूरे भारत की अदालतों ने उन्हें अरेस्ट कर अदालत में पेशी के लिए आवश्यक अरेस्ट वारंट जारी किए। विस्तृत जांच जुलाई 2021 में शुरू हुई और फ्रार हुए एक निदेशक और चीफ फाइनेंसियल ऑफ्सिर संजीव शुक्ला को गिरफ्तार कर इस वर्ष 27 सितम्बर को दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसे17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से अबतक दिल्ली स्थित सीजेएम और सेशंस कोर्ट नौ बार संजीव शुक्ला की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।निवेशकों का आरोप है कि इस बीच फंड की हेराफेरी करने के बाद राजीव और गीतिका गुप्ता विदेश भाग चुके हैं। निवेशकों द्वारा राजीव गुप्ता और उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है और उनका पासपोर्ट रद्द करने और अगस्त 2023 में होने वाले नवीनीकरण को अवरुद्ध करने की मांग की गई है।

सम्पादकीय

स्पष्ट और प्रभावी डाटा कानून जरूरी

डाटा सुरक्षा के नये विधेयक के मसौदे पर सरकार ने 17 दिसंबर तक सुझाव मांगा है. बजट सत्र में इस पर कानून बनाने की बात हो रही है. मौजूदा चुनावी प्रचार के कुछ रोचक मुद्दों से इसके महत्व को समझा जा सकता है. सत्ता पक्ष का दावा है कि देश में हो रहे बड़े पैमाने पर विकास को डाटा की सस्ती कीमत से समझा जा सकता है, जबकि विपक्षी नेता राहुल गांधी के अनुसार इवीएम की तर्ज पर सोशल मीडिया से भी चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र को प्रभावित किया जा सकता है.इन सब चुनावी भाषणों से परे बेंगलुरु में एक निजी संस्था ने लाखों लोगों के व्यक्तिगत संवेदनशील डाटा को इकट्ठा करने की कोशिश की, जिसकी जांच सरकार कर रही है. इंटरनेट आने के बाद भारत में 2000 में आइटी कानून बनाया गया. उसके बाद सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट आदि का विस्तार होने पर 2011 में आईटी इंटरमीडियरी नियम बनाये गये. जस्टिस एपी शाह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2012 में पहली बार डाटा सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार हुआ. आधार से जुड़े डाटा सुरक्षा पर विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की बेंच ने 2017 में प्राइवेसी के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया. उसके बाद जस्टिस श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2018 और फिर 2019 में नये कानून का ड्राफ्ट जारी हुआ. सरकार ने 2021 में नया बिल संसद में पेश किया, पर उसे वापस ले लिया गया. तब सरकार ने भ्रम और विरोधाभास दूर करने के लिए नया ड्राफ्ट बनाने की बात की थी. केंद्रीय आइटी मंत्री के अनुसार इस संतुलित कानून से भारतीय ग्राहकों को डिजिटल सुरक्षा मिलने के साथ स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को लाभ होगा. इससे ग्राहकों की सहमति के बगैर डाटा का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो पायेगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ग्राहकों का संबंध खत्म होने के बाद यूजर के निजी डाटा को हटाना होगा. बैंक में खाता खुलवाने के लिए सिर्फ केवाईसी के लिए जरूरी डाटा ही लिया जायेगा. कंपनियां बेवजह लोगों का निजी डाटा हासिल नहीं कर सकेंगी. इसके दो और प्रावधानों को बहुत ही प्रगतिशील बताया जा रहा है. अठारह साल से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग मानते हुए उनका डाटा हासिल करने के लिए अभिभावकों की स्वीकृति जरूरी होगी. इस बिल में पुरुष वाचक श्हीश् जैसे शब्दों के बजाय महिलाओं के लिए शी और हर जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना महिला सशक्तीकरण के लिहाज से प्रगतिशील माना जा रहा है. लेकिन पिछले दस सालों से हो रही विधायी मेहनत और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के गंभीर बिंदुओं का इस ड्राफ्ट में अभाव है. साल 2019 के बिल में अपराधों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करने के साथ कठोर दंड के प्रावधान थे, जिनका इसमें अभाव है. ग्राहकों के लिहाज से देखें, तो टेक कंपनियों से हर्जाना वसूलने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. उसके उलट गलत जानकारी देने या फिर गलत शिकायत करने पर आम ग्राहक पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. पुराने बिल में ग्राहकों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म में जाने के लिए डाटा पोर्टबिलिटी का प्रावधान था, जो इसमें नहीं है. सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिसरी को परिभाषित करने के लिए भी इसमें स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं. किसी भी डाटा सुरक्षा कानून को सफल बनाने के लिए इंटरनेट और टेक कंपनियों का भारत में रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए. इससे भारत के सभी कानून लागू करने के साथ उनके डिजिटल कारोबार से टैक्स की वसूली भी हो सकती है. लेकिन इस बारे में नया बिल मौन है. इस कानून को लागू करने के लिए डाटा सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान है, जिसके पास सिविल कोर्ट के पावर होंगे. लेकिन बोर्ड का गठन सरकार करेगी, जिससे उसके अधिकार और स्वायत्तता पर अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं. पुराने बिल के अनुसार डेटा के स्थानीयकरण के बारे में सख्त प्रावधान थे, जिन्हें अब खत्म कर दिया गया है. सरकार और जांच एजेंसियों को मिल रही छूट पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन निजी कंपनियों के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था नहीं बनने से यह कवायद अर्थहीन हो सकती है. साल 2021 के नये आइटी नियमों के अनुसार इंटरनेट कंपनियों को शिकायत, नोडल और कम्प्लाइंस अधिकारी की नियुक्ति करनी है. प्रस्तावित डेटा सुरक्षा कानून में दो और अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है. इतने तरह के अधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधान के बावजूद आम जनता, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को विदेशी टेक कंपनियों से कोई मदद नहीं मिलती है. डाटा कारोबार में मुनाफे के बड़े खेल को देखते हुए सरकार ने पुराने बिल में बड़ी कंपनियों के कारोबार के चार फीसदी तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया था. लेकिन अब कानून के उल्लंघन पर ढाई सौ करोड़ रुपये तक के जुर्माने के साथ सभी नियमों के तहत मिलकर अधिकतम 500 करोड़ का जुर्माना ही लग सकता है. विश्व के 194 में से 137 देशों ने डाटा सुरक्षा के बारे में प्रभावी कानून बनाये हैं. यूरोप में चार साल पहले लागू हुए जीडीपीआर कानून के अनुसार टेक कंपनियों पर अरबों डॉलर के जुर्माने लग रहे हैं. उन्हीं फैसलों का अनुसरण करते हुए भारत में कंपीटिशन कमीशन ने गूगल पर 2200 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है, जिसकी वसूली अभी बाकी है. लेकिन भारत में अगर यूरोपीय कानून की तर्ज पर सख्त डाटा सुरक्षा कानून नहीं लागू हुआ, तो फिर टेक कंपनियों पर जुर्माना और उसकी वसूली कैसे सफल होगी? आइपीसी और सीआरपीसी की तर्ज पर भारत को एक आधुनिक और प्रगतिशील डिजिटल संहिता की जरूरत है. अस्सी करोड़ से ज्यादा डिजिटल यूजर्स वाले भारत में डाटा सुरक्षा का कानून जनता और सरकार के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अहम है।

नमामि गंगे का परिवहन पहल

काशी और हल्दिया को उन्होंने जल मार्ग से जोड़ने की बात कही थी। आजादी के बाद पहली बार नमामि गंगे की सूत्रधार मोदी सरकार ने जल परिवहन की शुरुआत की है। यह काशी के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्धि है। इतना ही नहीं इसका फायदा पश्चिम बंगाल तक दिखाई देने लगा है। जितना सामान लेकर पानी का पहला जहाज आया उतना समान लाने के लिए सोलह ट्रक लगते। यह जल परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है।

साल 2014 के आम चुनाव में नरेन्द्र मोदी ने काशी में कहा था- मुझे मां गंगा ने बुलाया है। वो लंबे समय से पतित-पावन गंगा नदी को निर्मल और अविरल बनाने का सपना देख रहे थे। काशी और हल्दिया को उन्होंने जल मार्ग से जोड़ने की बात कही थी। आजादी के बाद पहली बार नमामि गंगे की सूत्रधार मोदी सरकार ने जल परिवहन की शुरुआत की है। यह काशी के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्धि है। इतना ही नहीं इसका फायदा पश्चिम बंगाल तक दिखाई देने लगा है। जितना सामान लेकर पानी का पहला जहाज आया उतना समान लाने के लिए सोलह ट्रक लगते। यह जल परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। यह कार्य आजादी के बाद से ही करना चाहिए था। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान सरकार द्वारा सैकड़ों नेशनल जल मार्ग पर कार्य किया जा रहा है। बिहार , झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सभी जल मार्ग से जुड़ रहे हैं। व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में गंगा के उस पार रामनगर में नवनिर्मित बहुउद्देशीय टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कोलकाता से चले मालवाहक जलयान एमवी रबीन्द्रनाथ टैगोर की अगवानी भी कर चुके हैं। आजादी के बाद यह पहला अवसर था, जब कोई जल मालवाहक इतना सामान लेकर इतनी दूरी तक आया था। मोदी ने जल परिवहन के विकास की असीम संभावनाओं को देखते हुए जो नीतिगत फैसले किए हैं, उनकी योजनाओं को रिकार्ड समय में पूरा किया जा रहा है। वाराणसी का मल्टी मॉडल टर्मिनल परिवहन के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुआ। जल मार्ग विकास परियोजना के तहत बने इस टर्मिनल को हल्दिया-वाराणसी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर विकसित किया गया है। इस टर्मिनल के जरिये दो हजार टन के बड़े जहाजों की भी आवाजाही मुमकिन है। मल्टी मॉडल टर्मिनल जल परिवहन को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा था। यह गंगा नदी पर बने पहले तीन ऐसे टर्मिनल में से था। बनारस की कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। इससे पूर्वांचल के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ जाने का रास्ता आसान हुआ है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा हल्दिया से प्रयागराज तक जलमार्ग विकसित हुआ है। परियोजना के तहत पहले बंदरगाह का शुभारंभ भी मोदी ने किया। गंगा में जल मार्ग से बिहार, छत्तीसगढ़ के रास्ते पश्चिम बंगाल तक उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। देश में पैंसठ प्रतिशत माल की ढुलाई सड़क मार्ग से और सत्ताईस प्रतिशत रेलवे के जरिये होती है। जल परिवहन का हिस्सा केवल आधा प्रतिशत है। इसके विपरीत विकसित देशों में यह करीब दस प्रतिशत है। जल परिवहन ढाई गुना सस्ता पड़ेगा। प्रदूषण भी नहीं होगा। सड़क मार्ग से एक टन प्रति किलोमीटर माल भाड़ा ढाई रुपये पड़ता है। रेल का माल भाड़ा एक रुपया चालीस पैसे है। जल परिवहन पर यह शुल्क केवल एक रुपया छह पैसे होगा। सड़क मार्ग से एक लीटर ईंधन में प्रति किमी चौबीस टन और रेलवे के जरिये 85 टन माल की ढुलाई होती है। जबकि जल परिवहन में एक लीटर से प्रति किमी करीब सौ टन माल ले जाया जा सकता है। इस जलमार्ग पर वाराणसी के अलावा ग़ाज़ीपुर, कालूघाट, साहिबगंज, त्रिवेणी और हल्दिया में बहु उद्देशीय टर्मिनल होंगे। जलयानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए डोरीगंज बिहार में एक केंद्र होगा। पांच स्थानों पर रोल ऑन रोल रो-रो केंद्र होंगे जो सड़क से जल टर्मिनल तक माल की आवाजाही की सुविधा प्रदान की गई थी। वाराणसी के रविदास घाट पर गंगा नदी में तैयार की गई जेट्टियों का लोकार्पण एवं शिलान्यास हो चुका है। वाराणसी, अयोध्या एवं मथुरा के लिए हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रिक कैटामेरान का अनुबन्ध तथा वाराणसी एवं डिब्रूगढ़ के मध्य क्रूज की समय-सारिणी का विमोचन भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि जल परिवहन के प्रारम्भ होने से रेलवे तथा सड़कों के भार को कम करने में मदद मिलेगी। इससे डीजल की खपत को कम करते हुए प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। इस प्रकार इसके माध्यम से अनेक लाभ प्राप्त होंगे। इन लाभों का केन्द्र बिन्दु काशी बनने जा रहा है। सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। जल परिवहन के माध्यम से पर्यटन के साथ ही, कार्गो की सुविधा लोगों को प्राप्त होगी।उत्तर प्रदेश देश में परम्परागत उत्पाद, एमएसएमई का सबसे बड़ा केन्द्र है। मुख्यमंत्री का यह भी मानना कि उत्तर प्रदेश में नब्बे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उद्यमी तथा उद्योग हैं। उनके उत्पादों को उत्तर प्रदेश के बाहर देश के अन्य भागों में तथा दुनिया के बाजार में पहुंचाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उत्पादों की लागत पोर्ट तक पहुंचते-पहुंचने काफी ज्यादा हो जाती थी। पहले प्रदेश की नदियों में जल परिवहन की सुविधा थी। इसके माध्यम से यहां पर कोयला आता था और गुड़, चीनी, फल, सब्जियां, अनाज तथा खाद्यान्न यहां से बाहर जाता था। हिमालय से आने वाली नदियों में विशेषकर बरसात के मौसम में सिल्ट काफी मात्रा में आता है। इसकी डिसिल्टिंग नहीं की गई। परिणामतः नदियां छिछली होती गई। उनका दायरा बढ़ता गया। जल परिवहन का स्थान सड़क तथा अन्य परिवहन माध्यमों ने ले लिया। यह महंगा होने के साथ ही, सभी के लिए सुगम भी नहीं था। इसका परिणाम हुआ कि यहां के उत्पाद यहीं तक सीमित रह गये। एमएसएमई उद्योग का भी नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से हल्दिया के बीच पहला राष्ट्रीय जलमार्ग दिया। भदोही तथा मीरजापुर की कालीन, चन्दौली का ब्लैक राइस, जौनपुर के वूलेन कारपेट, गाजीपुर का जूट वॉल हैंगिंग, मऊ के पावरलूम टेक्सटाइल्स, मीरजापुर के ब्रास प्रोडक्ट, प्रयागराज के मूंज और फूड प्रोसेसिंग के उत्पाद तथा वाराणसी की सिल्क साड़ियां इन सभी को यहां से शिप पोर्ट तक भेजने में मदद मिली। एक वर्ष में वाराणसी तथा आसपास के जनपदों से सैंतीस सौ करोड़ रुपये के ओडीओपी उत्पादों का निर्यात किया गया। इससे यहां के उद्यमियों, कारीगरों, किसानों तथा हस्तशिल्पियों को कार्य मिला और उन्हें मुनाफा भी प्राप्त हुआ। **-एजेंसी**

जीएम सरसों की खेती नुकसानदेह

मई, 2017 में भी जीइएसी ने इसी किस्म को हरी झंडी दी थी, लेकिन किसानों और वैज्ञानिकों के भारी विरोध के कारण सरकार ने सिफारिश मानने से मना कर दिया था. बताया जा रहा है कि यह किस्म प्रो दीपक पेंटल द्वारा देश में विकसित की गयी है और पूर्णतरू स्वदेशी है. यह भी दावा है कि यह जीएम सरसों 26 प्रतिशत अधिक उपज देगी. तर्क है कि देश में खाद्य तेलों का उत्पादन कम है, जिसके कारण देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है. जीएम सरसों को उपभोक्ताओं, किसानों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी बताया जा रहा है।

अक्तूबर 18, 2022 को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रैजल कमेटी (जीइएसी) ने जीएम सरसों की एक किस्म डीएमएच-11 को एक बार फिर खेतों में लगाने की सिफारिश की है. मई, 2017 में भी जीइएसी ने इसी किस्म को हरी झंडी दी थी, लेकिन किसानों और वैज्ञानिकों के भारी विरोध के कारण सरकार ने सिफारिश मानने से मना कर दिया था. बताया जा रहा है कि यह किस्म प्रो दीपक पेंटल द्वारा देश में विकसित की गयी है और पूर्णतरू स्वदेशी है. यह भी दावा है कि यह जीएम सरसों 26 प्रतिशत अधिक उपज देगी. तर्क है कि देश में खाद्य तेलों का उत्पादन कम है, जिसके कारण देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है. जीएम सरसों को उपभोक्ताओं, किसानों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी बताया जा रहा है. लेकिन जीइएसी के इन दावों का सच क्या है, वह इससे स्पष्ट है कि स्वयं समिति ने अनुमति देते हुए कुछ ऐसी शर्तें लगायी हैं, जो यह साबित करती हैं कि जीइएसी के पास इस बीज के सुरक्षित होने के कोई प्रमाण नहीं हैं, और वह शर्तें लगाकर इसके दुष्प्रभावों के आरोप से बचना चाहती है, कि भविष्य में वह कह सके कि हमने जीएम सरसों को कुछ शर्तों के साथ ही अनुमति दी थी और चूंकि उन शर्तों का पालन नहीं हुआ, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है. गौरतलब है कि जो शर्तें लगायी गयी हैं, उनका अनुपालन करना सरकार के बस की बात नहीं है.इस दावे में सत्यता नहीं है कि डीएमएच-11 एक स्वदेशी खोज है. वर्ष 2002 में बॉयर (एक विदेशी कंपनी) की एक सहायक कंपनी 'प्रोएग्रो सीड कंपनी' ने ऐसी ही एक किस्म, जिसे डीएमएच-11 कहा जा रहा है, की अनुमति हेतु आवेदन किया था, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि इससे बेहतर उत्पादकता मिलने का कोई प्रमाण नहीं है. वास्तव में डीएमएच-11 किस्म बारनेस और बारस्टार नाम के दो जींस को जोड़कर बनायी गयी है और यह जींस बॉयर क्रॉप साइंस द्वारा पेटेंट की गयी है. इस तथ्य को छुपाया गया है और भविष्य में बॉयर कंपनी अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों की एवज में भुगतान मांग सकती है और किसान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. डीएमएच-11 के बारे में जीइएसी का ज्यादा उत्पादकता का दावा सही नहीं है क्योंकि भारत के सरसों एवं रेपसीड शोध संस्थान का कहना है कि देश में डीएमएच-11 से कम से कम 25 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादकता देने वाली किस्में पहले से ही विकसित की जा चुकी हैं. सरकार को उन किस्मों को बढ़ावा देना चाहिए. खेद का विषय यह है कि केवल इस प्रौद्योगिकी के विदेशी मूल को ही नहीं छुपाया गया, बल्कि यह तथ्य भी छुपाया गया कि जीएम सरसों हर्बीसाइड टोलरेंट भी है यानी शाकनाशी सहिष्णु भी है. डीएमएच-11 का ट्रायल करते हुए उसकी इस विशेषता के बारे में कोई टेस्ट नहीं किया गया. सतर्क नागरिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा सच को सामने लाने के कारण अब जीइएसी ने एक नया रास्ता खोजा है कि अनुमति के साथ यह शर्त लगायी गयी है कि किसी भी हालत में किसानों द्वारा किसी शाकनाशी का उपयोग नहीं किया जायेगा. अब चूंकि यह किस्म ही शाकनाशी सहिष्णु है, स्वाभाविक तौर पर शाकनाशियों की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण कोई सरकारी एजेंसी किसानों को इसके बारे में रोक नहीं सकती. इस संबंध में एक समानांतर उदाहरण हमारे सामने है कि ग्लाइफोसेट नाम के शाकनाशी का उपयोग केवल चाय बागानों और गैर कृषि क्षेत्रों में ही हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद देशभर में यह धड़ल्ले से बिकता है और भारत में उसकी कुल बिक्री 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा है. समझा जा सकता है कि जीइएसी का यह कृत्य वास्तव में अनैतिक है. कई प्रकार के शाकनाशकों के दुष्परिणामों से दुनिया जूझ रही है. इनके कारण अमरीका और अन्य मुल्कों, जहां ऐसी किस्मों का इस्तेमाल हो रहा है, में कैंसर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और शाकनाशकों की निर्माता कंपनियों पर मुकदमे भी लगातार बढ़ रहे हैं. शाकनाशी सहिष्णु किस्म का सही मूल्यांकन नहीं करना वैज्ञानिक धोखा और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है. कई आयुर्वेदिक औषधियों में भारतीय सरसों एक वरदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है. इसकी खुशबू एवं स्वाद ही इसकी विशेषताएं हैं. जानकार बताते हैं कि डीएमएच-11 में न तो खुशबू होगी और न ही स्वाद यानी इसमें औषधीय गुण होने का सवाल ही नहीं है. स्वाद की दृष्टि से सरसों का साग पूरी दुनिया को आकर्षित करता है. जब डीएमएच-11 उगायी जायेगी, तो सरसों के साग के साथ उगने वाले

बथुआ और पालक जैसे अन्य साग भी गायब हो जायेंगे. ये साग लगभग मुफ्त में खेतों से निकाले जाते हैं और वे भारतीय महिलाओं के लिए आयरन का एक प्रमुख स्रोत हैं. इनके समाप्त होने से देश में एनीमिया की समस्या ज्यादा बढ़ सकती है. कहा जा रहा है कि इस किस्म के लगाने से देश में खाद्य तेलों का आयात कम हो जायेगा, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस किस्म के आने से शाकनाशकों का आयात जरूर बढ़ सकता है।**-एजेंसी**

आलेख

समझौतों का विस्तार

ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इस समझौते को हरी झंडी दे दी है. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिज ने बड़े उत्साह से इस मंजूरी की घोषणा की है. उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले बाली में आयोजित जी-20 समूह के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी थी कि वे अगले वर्ष मार्च में भारत की यात्रा करेंगे. बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंधों में बड़ी निकटता आयी है।

विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध स्थापित करने के क्रम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते की स्वीकृति महत्वपूर्ण चरण है. ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इस समझौते को हरी झंडी दे दी है. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिज ने बड़े उत्साह से इस मंजूरी की घोषणा की है. उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले बाली में आयोजित जी-20 समूह के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी थी कि वे अगले वर्ष मार्च में भारत की यात्रा करेंगे. बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंधों में बड़ी निकटता आयी है. अमेरिका और जापान के साथ भारत एवं ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड समूह के सदस्य हैं तथा इनके बीच सामरिक संबंध भी गहरे हो रहे हैं, जिसका एक बड़ा उदाहरण हर वर्ष होने वाला मालाबार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है. इस क्रम में जहां पिछली सरकार के समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौतों को साकार करने का प्रयास हो रहा है, वहीं अनेक नये समझौतों पर भी सहमति बनी है. पिछले साल अगस्त में सरकार ने सभी भारतीय दूतावासों एवं उच्चायोगों को निर्देश दिया था कि वे निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं का अध्ययन करें तथा समुचित उपाय सुझायें. भारत सरकार ने 2030 तक निर्यात को दो ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को निर्माण और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि हम न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति भी कर सकें. प्रधानमंत्री मोदी ने देश से भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भागीदार बनाने की दिशा में काम करने का बार-बार आह्वान किया है. भारत ने विदेशी उद्योगों और निवेशकों को भी भारत आने का आमंत्रण दिया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं. इन कवायदों में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों की अहम भूमिका है. ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से समझौते के प्रयास पिछली सरकार के समय शुरू हुए थे, पर वे साकार नहीं हो सके थे. अब ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हो जाने के बाद यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ लंबित प्रस्तावों से जुड़ी उम्मीदें भी बढ़ गयी हैं. इस वर्ष फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है, जो मई से प्रभावी हो गया है. वैश्विक राजनीति और आर्थिकी के मंचों पर भारत की भूमिका का विस्तार हो रहा है. इसका लाभ व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में भी मिल रहा है, जो उत्साहजनक है।**-एजेंसी**

दैनिक राशिफल

मेषः- सामाजिक गतिविधियों में आपकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। नये लक्ष्य एवं नये कायरें में ब्यस्तता बढ़ेगी। आर्थिक क्षेत्र में परिश्रम का पूरा लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सतर्कता बरते।

बृषभः- सामाजिक संबंधों में ब्यस्तता बढ़ेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। कुछ नये संबंधों के प्रति मन उत्साहित होगा। रोजगार में लाभकारी स्थिति मन को खुश रखेगी।

मिथुनः- कुछ नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे। सभी इच्छाओ को सकार करने से पूर्व गहन सोच-विचार करें। आकस्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। घर में खुशहाली रहेगी।

कर्क :-महत्वपूर्ण कायरें की समयानुकूल पूर्ति हेतु मन चिंतित होगा। प्रतिभाओ पर भरोसा रख महत्वपूर्ण लक्ष्यों को फलीभूत करने हेतु केंद्रित हों। ग्रहों की अनुकूलता प्रगति के अवसर प्रदान करेगी।

सिंहः- अपने पद एवं मर्यादा ख्याल रखते हुए उच्छृंखल मन को नियंत्रित करें। आकस्मिक कोई सुखद समाचार से मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी के साथ मधुरता कायम रखें।

कन्याः- कोई नयी इच्छा मन पर प्रभावी होगी। सामान्य दिनर्चया के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा। कार्यक्षेत्र में ब्यस्तता बढ़ेगी। अपने स्वास्य के प्रति सचेत रहें। जरूरी कार्य समय से पूर्ण करें।

तुलाः- निराशावादी विचार योजनाओं की सार्थकता में बाधक हैं। एक साथ कई चिंताओं से मन ग्रसित होगा। अभिभावको एवं श्रेष्ठजनो के सहयोग से समस्याएं हल होंगी। जीवन साथी से मधुरता कायम रखें।

वृश्चिकः- नई प्रतिभाएं उजागर होंगी। प्रिय लोगों का सानिध्य मिलेगा। शिक्षा-प्रतियोगिता की दिशा में मन उसके परिणाम हेतु चिंतित होगा। रोजगार में लाभकारी स्थिति खुश रखेगी।

धनुः- वाक्यपटुता एवं व्यवहार कुशलता से संबंधों में प्रभावी होंगे। भौतिक आकांक्षाएं सार्थकता हेतु मन को उद्वेलित करेंगी। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु मन केंद्रित होगा। रोजगार में व्यस्तता रहेगी।

मकरः- कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। भावुकता व्यावहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक होगी। अतरू इसमें सुधार लायें। घर में किसी मेहमान के आगमन से व्यय संभव।

कुंभः- नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे। कार्यक्षेत्र में अनवरत् व्यस्तता रहेगी। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। घर-परिवार में वातावरण उत्साहित होगा।

मीनः- नये कायरें के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा। काफी दिनों से अवरोधित कोई कार्य हल होने की संभावना है। कल्पनाओं में जीना छोड़ भौतिक जगत के अनुकूल चलने का प्रयास करें।

12 साल बाद वो जेल से छूटा मैले कुचैले कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा.

घर पहुंचते ही बीबी चिल्लाई:

कहां घूम रहे थे इतनी देर?

आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना?

वो आदमी वापिस जेल चला गया.

आज का सुविचार

:- सुविचार :-

रिश्तों में न रखा करो हिसाब नफे और नुकसान का जिंदगी की पाठशाला में गणित का कमजोर होना अच्छा है....

संक्षिप्त समाचार

डीएम ने की कलक्ट्रेट सभागार में बैठक, बोले,नष्ट हुए पौधों के स्थान पर नए पौधे रोपित करें विभाग

बहराइच, (यूएनएस)। जिले में वृक्षारोपण अभियान के दौरान रोपित किए गए पौधों की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने निर्देश दिया कि 26 से 30 नवम्बर 2022 के मध्य अभियान संचालित कर नष्ट हुए पौधों के स्थान नये पौधे रोपित कर दिए जाए। डीएम ने यह भी बताया कि सम्बन्धित विभाग वन विभाग की नर्सरी से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। बैठक के दौरान डीएम डॉ. चन्द्र ने निर्देश दिया कि अब तक पौधे रोपण की जियो टैगिंग न करने वाले विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वेतन बाधित करने की कार्यवाही की जाय। डीएम ने सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिया कि रोपे गए पौधों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच संजय शर्मा, कमाण्डेन्ट एसएसबी 42वीं बटालियन तपन कुमार दास व 59वीं के स्वर्णजीत शर्मा, डीपीआरओ उमाकान्त पाण्डेय, जिला उद्यान अधिकारी पारसनाथ, प्रभारी कृषि विज्ञान केन्द्र डॉ. बी.पी. शाही सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

दिव्यांग बच्चों ने लहराया परचम,मानसिक मंदित बच्चों की टीमों ने प्रतिभाग, जीते 19 मेडल

बहराइच, (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय स्पेशल गेम 2022 का आयोजन साहस स्पोर्ट्स लखनऊ के द्वारा आयोजित किया गया। जिसमें लखनऊ के सभी मानसिक मंदित बच्चों के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं के साथ-साथ बहराइच, आगरा तथा कानपुर के मानसिक मंदित बच्चों की टीमों ने प्रतिभाग किया। बाबा सुंदर सिंह बधिर विद्यालय के 14 बच्चे बहराइच से लखनऊ चलकर के.डी .सी बाबू स्टेडियम पहुंचे और अपने जैसे दिव्यांग बच्चों के साथ प्रतिभाग किया तथा दिव्यांग बच्चों ने 19 मेडल प्राप्त किए। इसमें तीन गोल्ड ,9 सिल्वर व 7कास्य पदक प्राप्त किए 50 मीटर दौड़ में आयुषी मिश्रा गोल्ड ,अर्चना चौहान सिल्वर 100 मीटर दौड़ में जुनेद अजीज सिल्वर, गुरमिंदर सिंह सिल्वर राज पांडे कास्य , मोहम्मद दानिश कास्य ,आयुष जयसवाल कास्य 50 मीटर वाक में जामिन रजा कास्य सॉफ्ट बॉल थ्ो में अमन यादव गोल्ड, आयुषी मिश्रा गोल्ड ,हीना सिल्वर, मोहम्मद दानिश सिल्वर, गुरमिंदरसिंह सिल्वर, खुशी सिल्वर ,अर्चना चौहान कांस्य, जुनेद अजीज कास्य शॉट पुट में रितेश शुक्ला सिल्वर, प्रांशु गुप्ता सिल्वर ,अमिताशा सिन्हा कास्य, हीना ,अमन यादव, राज पांडे तथा जामिन रजा को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ । दिव्यांग बच्चों के साथ विद्यालय प्रबंधक डॉ बलमीत कौर तथा विद्यालय स्टाफ सोनी व गीता श्रीवास्तव कार्यक्रम की आयोजिका डॉ सुधा बाजपेई तथा मुख्य कार्यकारी मोहम्मद एजाज रहें।

ओबीसी मोर्चा ने फूंका डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का पुतला

बस्ती, (यूएनएस)। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक द्वारा नाई समाज के प्रति जाति सूचक अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। शास्त्री चौक पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए डिप्टी सीएम का पुतला फूंका। पुतला दहन के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे बुझाया, लेकिन तब तक पुतला जल चुका था। इसके बाद मोर्चापदाधिकारी, कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस की श्क्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे, राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन डीएम के प्रशासनिक अधिकारी को सौपा। ज्ञापन में डिप्टी सीएम को तत्काल पद से बर्खास्त किए जाने की मांग की गई है। मोर्चा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एक चौनल के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक द्वारा नाई समाज को जाति सूचक, अभद्र टिप्पणी किए जाने से आक्रोशित दिखे। ओबीसी मोर्चा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष ठाकुर प्रेमनंदवंशी ने कहा कि डिप्टी सीएम ने नाई समाज के लिए जो अशोभनीय, अमर्यादित टिप्पणी की है, वह किसी भी दशा में उचित नहीं है। राष्ट्रपति से डिप्टी सीएम को तत्काल पद से बर्खास्त करने की मांग किया। कहा कि यदि डिप्टी सीएम को उनकी अमर्यादित, अशोभनीय टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। चेतावनी दिया कि यदि उन्हे पद से बर्खास्त नहीं किया गया तो नाई समाज के लोग राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश में जनान्दोलन करने को बाध्य होंगे। पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन करने वालों में हृदय गौतम, साधना गौतम आजाद, कालिका प्रसाद राठौर, आरके आरतियन, प्रदीप कुमार ठाकुर, बुद्धेश राना, ठाकुर राम किशोर, राम सुमेर यादव, विनय कुमार, राजमणि चौधरी व अन्य शामिल रहे।

यातायात नियमों का पालन करने के लिए छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक

बस्ती, (यूएनएस)। जिले के हरैया तहसील क्षेत्र में यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कप्तानगंज थाना क्षेत्र के संत कबीर इंटर कालेज, पिकौरा व प्रताप एजुकेशनल एकेडमी पिकौरा में बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। महराजगंज चौकी प्रभारी सर्वेश कुमार ने यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत क्षेत्र के तमाम विद्यालयों में पहुंचकर स्कूली छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे जागरूक करते हुए उन्हें यातायात नियमों के बारे में बताया। चौकी प्रभारी ने कहा कि वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ निर्धारित गति-सीमा में पूरी सतर्कता एवं सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। सर्दी के मौसम में कुहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप एवं फॉग लाइट का प्रयोग करे। बिना लाइसेंस के हमें बाहर नहीं चलानी चाहिए तथा बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। साथ ही चार पहिया वाहन चलाते समय चालक व बैठे लोगों को सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि सड़क पर गलत तरीके से व अनावश्यक वाहन न खड़ा कर, अपने वाहन को खड़ा करने के लिए हमेशा निर्धारित पार्किंग स्थल का ही प्रयोग करना चाहिए। कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न कर तथा ओवरलोडिंग से बचने,वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को कम करने का अनुरोध करते हुए यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि आप सभी के जागरूक होने वा एक छोटे से प्रयास के चलते आए दिन होने वाले सड़क दुर्घटना हादसे में होने वाली मौतों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही प्रत्येक बच्चे से अपने अभिभावकगणों के साथ-साथ 5 अन्य व्यक्तियों को भी यातायात के नियमों को बताकर, इस मानव श्रृंखला को आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित किया गया। समस्त छात्र एवं विद्यालय के अध्यापक, विद्यालय वाहन चालकों एवं समस्त स्कूल स्टॉफ को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर वरिष्ठ शिक्षक धनीष त्रिपाठी, सतीश रंजन सिंह, अर्जुन यादव,जगदीश सिंह,अरुण कुमार,सीपी मिश्रा, सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

रंजिश में युवक की मौत, गांव में विवाद के बाद चले पत्थर, 2 की हालत गंभीर

बहराइच, (यूएनएस)। जिले में रामगांव थाना क्षेत्र में मेटुकहा चौराहे पर रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में विवाद के बाद पथराव शुरू हो गया। जिसमें एक कि मौत हो गई। जबकि दो लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राम गांव थाना क्षेत्र के तारापुर मेटुकहा गांव निवासी गुल्ले उर्फ मुजीबुर्रहमान और लियाकत अली के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जाता है कि शुक्रवार को मेटुकहा चौराहे पर दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। देखते-देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के बीच ही ईंट और पत्थरों से पथराव शुरू हो गया। मारपीट में गुल्ले (40) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि लियाकत समेत दो घायल हो गए। लियाकत की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी जयप्रकाश त्रिपाठी और प्रभारी निरीक्षक समेत काफी संख्या में पुलिस बल पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रंजिश में मारपीट और पथराव हुआ है। जिसमें एक युवक की मौत हुई है। मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं।

03 दिसम्बर को विश्व दिव्यांग दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण करेगी उ0प्र0 सरकार

- 12 विभिन्न श्रेणियों में चयनित दिव्यांगजनो को किया जाएगा सम्मानित
- दिव्यांगजनों को सम्मान देकर प्रोत्साहित कर मुख्यधारा से जोड़ेगे दिव्यांगजन : नरेन्द्र कश्यप

न्यूज गाइड । संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वंत्रत प्रभार) नरेन्द्र कश्यप जी की अध्यक्षता में विश्व दिव्यांग दिवस 03 दिसम्बर, 2022 के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण एवं सम्मान हेतु पात्र आवेदनकर्ताओं के चयन किये जाने हेतु चयनित समिति की बैठक विधानसभा में स्थित कार्यालय में आयोजित की गयी। बैठक में समस्त जिलों से आये पात्र आवेदनकर्ताओं के नामों के चयन पर विचार-विमर्श किया गया। दिव्यांगजन मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं उनको शिक्षित कर सभ्यता की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए उ0प्र0 सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके प्रति गम्भीरता से कार्य कर रही है। इसी आधार में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन करने के लिए समाज की उन्नति के लिए दिव्यांगजनों द्वारा किये गये कार्यो को पुरस्कृत व सम्मानित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। केन्द्र व प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांगों को दिये जाने वाले लाभाविन्त योजनाएं सुलभ व सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 03 दिसम्बर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि जैसे जीवन के हर पहलू में दिव्यांग व्यक्तियो के अधिकारों तथा उनके हितों की प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करता है। 'विश्व दिव्यांग दिवस' पुरस्कार राज्य स्तर पर दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों व स्वनियोजित दिव्यांगजन, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति व संस्था, प्रेरणास्त्रोत, सृजनशील दिव्यांग बालक व बालिका, दिव्यांग खिलाड़ियों, दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए, दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवायें प्रदान करने वाले श्रेष्ठ जिला आदि कुल 12 विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं।

आयोजित की गयी समिति की बैठक में हेमन्त राव, अपर मुख्य सचिव, अजीत कुमार, विशेष सचिव एवं राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, सत्य प्रकाश पटेल, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कुलपति, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, रमेश पाण्डेय, कार्यालय प्रभारी, क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र, लखनऊ, अमिताभ शुक्ला, प्रबन्धक, भागीरथ सेवा संस्थान, गाजियाबाद आदि उपस्थित रहे।

शिवगढ़ राजा बाजार-आईटीआई तिरहा सम्पर्क मार्ग गड्ढों में तब्दील, चलना हुआ दुश्वार

न्यूज गाइड। संवाददाता

शिवगढ़, रायबरेली। शिवगढ़ क्षेत्र का शिवगढ़ राजा बाजार - रामपुर खास आईटीआई तिराहा सम्पर्क मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गया है। जिस पर साइकिल, मोटरसाइकिल से चलना तो दूर की बात पैदल चलना भी किसी चुनौती से कम साबित होता है। आलम यह है कि हल्की बारिश होते ही पूरा सम्पर्क मार्ग जलाशय में तब्दील हो जाता है। जिस पर स्कूली छात्र,छात्राओं एवं राहगीरों का गिर कर आए दिन चोटिल होना बिल्कुल आम बात हो गई है। गौरतलब हो कि 1 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र के शिवगढ़ राजा बाजार - रामपुर खास आईटीआई तिराहा सम्पर्क मार्ग में इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं कि इस सम्पर्क से कोई मारुति कार,आटो रिक्सा,टैक्सी निकल पाना सम्भव नहीं है। सड़क को देखकर यहा अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इसी सम्पर्क मार्ग पर केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय स्थित होने के चलते इस सम्पर्क मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों छात्र-छात्राओं का आवागमन रहता। इसके साथ ही शिवगढ़ कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, श्री बरखण्डी महाविद्यालय, श्री बरखण्डी विद्यापीठ इण्टर कॉलेज, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, राजकीय बीज भण्डार, कृषि रक्षा इकाई,विद्युत उपकेंद्र स्थित होने के चलते स्कूली छात्र-छात्राओं, राहगीरों एवं मरीजों का आवागमन रहता है। कांग्रेस से जिला पंचायत सदस्य अंजली पासी ने कहाकि सरकार सड़कों के गड्ढा मुक्त होने का दावा करती हैं किंतु आलम यह है कि क्षेत्र की अधिकांश सड़कें गड्ढों में तब्दील है। उन्होंने कहा कि सरकार की नजरों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं ये आंकड़े किताबी हैं। पीडब्लूडी विभाग की उदासीनता के चलते पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुके इस संपर्क मार्ग पर आए दिन कोई न कोई गिरकर चोटिल होता रहता है। इस सम्बंध में जब पीडब्लूडी विभाग के एई अनिल कुमार अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर लम्बे इस सम्पर्क मार्ग को बनाने के लिए बारिश से पूर्व ही टेंडर उठ गया था किंतु ठेकेदार का निधन हो गया था। जिसके चलते यह सम्पर्क मार्ग नहीं बन सका। दोबारा टेंडर उठ गया है जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

मीडिया समाज एवं सरकार का आइना: गन्ना विकास राज्य मंत्री

मंत्री के समक्ष गिनाई गई सूचना विभाग की अनियमिततायें

लखनऊ, (यूएनएस)। गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा है कि मीडिया समाज एवं सरकार का आइना है। पत्रकार द्वारा लिखे एवं दिखाये गये समाचारों पर आम जनमानस पूर्ण विश्वास करता है। हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि जनता के बीच हमारा विश्वास कायम रहे। वे उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन (पंजीकृत) द्वारा पीलीभीत जिले में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उक्त जानकारी देते हुए यूनियन के प्रवक्ता शशिकांत पांडेय ने बताया कि यूपी के राज्यमंत्री की मौजूदगी में आयोजित पत्रकारों के अधिवेशन में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष डा. राजेश त्रिवेदी ने अपने संबोधन में यूपी के पत्रकारों की समस्यायें गिनाते हुए सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में व्याप्त अनियमितताओं को रेखांकित किया। जनपद पीलीभीत के छतरी चौराहा स्थित निर्मल होटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजेश त्रिवेदी एवं महामंत्री रमेश शंकर पांडेय ने सर्वसम्मति से पीलीभीत उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष पद पर असित शुक्ला एवं महामंत्री विवेक अवस्थी को घोषित किया। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नीरज मिश्रा को मंडल अध्यक्ष बरेली एवं पत्रकार सुधीर दिक्षित को मंडल उपाध्यक्ष बरेली बनाया गया है। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में उत्तर प्रदेश गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने शिरकत की। प्रथम सत्र में सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर सतीश चंद्र शुक्ल मंचासीन रहे। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं से पूरी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करने की अपील की गई है।

आयोजित हुई स्वास्थ्य कार्यशाला,सीएमओ बोले, किशोर किशोरियों के साथ रखें मैत्रीपूर्ण व्यवहार

उरई/जालौन, (यूएनएस)। स्वास्थ्य विभाग एवंपापुलेशन सर्विसेज इंडिया (पीएसआई) इंडिया द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर किशोरियों केसाथ मैत्रीपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में आयोजित इस प्रशिक्षण में शहरी क्षेत्र के चिकित्सक और स्टाफ नर्स ने भाग लिया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी शहरी स्वास्थ्य डॉ एस. डी चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले किशोर किशोरियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाना अनिवार्य है। उन्हें अपनी बात करने में हिचक न हो, और उनकी बातें गोपनीय रखी जाये, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि वह जो भी बातें यहां बता रहे है, वह बेहद गोपनीय रहेगी। उनकी बातें लिखने की बजाय मानसिक रुप से सुनी जाए और उसका मानसिक तौर पर जवाब भी दिया जाए। जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम डॉ. प्रेमप्रताप ने बताया कि स्वास्थ्य इकाइयों में आने वाले किशोर किशोरियों परअपना निर्णय न थोपे। बल्कि उनकी बातों को सुने और उन्हें उचित परामर्श दें और निर्णय उनके ऊपर ही छोड़ दे। पीएसआई इंडिया संस्था की राज्य प्रतिनिधि ईप्शा सिंह ने एक कहानी के माध्यम से किशोर किशोरियों की काउसंलिंग का तरीका समझाया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में किशोर किशोरियों के लिए मैत्रीपूर्ण माहौल का सृजन किया जाना चाहिए। इसका स्वास्थ्य केंद्र परिसर में व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि किशोर किशोरी बिना हिचक अपनी बात कह सके। उन्हें सुरक्षित गर्भनिरोधक साधनों के बारे में भी समझाया जाए। शहरी स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर संजीव कुमार चंदेरिया, डीईआईसी मैनेजर रवींद्र सिंह चौधरी, जिला परामर्शदाता क्वालिटी एश्योरेंस डॉ अरुण कुमार, नगरीय प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ जितेंद्र कुमार, डॉ सहन बिहारी गुप्ता, डॉ अभिलाष, डॉ विष्णु, डॉ एमसी वाजपेयी, पीएसआई इंडिया के शरद श्रीवास्तव, चौबे सिंह, ज्ञानप्रकाश पांडेय, ऊषा, उमा, रचना, कल्पना, सरोज गौर आदि मौजूद रहे।

चिकित्सकों द्वारा जेनरिक व पेटेंट दवाएं ना लिखने से मोनोपोली दवाओं से लुट रहे मरीज

कानपुर देहात, (यूएनएस)। लोगों के बीमार पड़ने से उनकी सेहत तो बिगड़ती ही है लेकिन डाक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली मोनोपोली दवाएं मध्यमवर्गीय या गरीब परिवार में बीमार पड़ने वाले मरीज के इलाज कराने में उनके परिजनों की कमर भी तोड़ देती है। नर्सिंगहोमों एवं फेमस डॉक्टर के यहां मोनोपोली दवाओं का खेल चल रहा है। कई अस्पतालों में मेडिकल स्टोर भी बिना फार्मेसिस्ट के रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं। इनमें आने वाले रोगियों के पर्चे पर जो दवाएं लिखी जाती है बाहर के मेडिकल मेडिकल स्टोरों पर नहीं मिलती हैं। इन दवाओं पर एमआरपी बहुत अधिक प्रिंट होती है जबकि उसी साल्ट की दवाएं बाहर काफी कम मूल्य पर मिलती हैं। जबकि सरकार ने दवा के पर्चे पर साल्ट लिखने का आदेश जारी कर रखा है लेकिन इसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दवा के नाम पर रोगियों की जेब पर डाका डालने का यह खेल नर्सिंगहोमों से लेकर क्लीनिकों और सरकारी अस्पतालों तक में खेला जा रहा है। हैरत की बात तो यह है कि दवाओं के नाम पर गड़बड़ी रोकने की जिसकी जिम्मेदारी है उसे यह भी नहीं पता है कि कितने नर्सिंगहोमों में मेडिकल स्टोर संचालित हैं। दवा के नाम पर रोगियों को जेब नहीं ढीली करनी पड़ रही बल्कि तमाम डाक्टर और अस्पताल मिलकर जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस खेल से अनजान रोगी के तीमारदार बाजार में सस्ती दर पर मिलने वाली दवाओं का तीस से पचास गुना अधिक पैसा अस्पतालों को अदा करते हैं। दवाओं में कमाई के इस खेल में बड़ी दवा कंपनियों और उनके डीलरों के साथ अस्पताल और डाक्टर के बीच समझौते के तहत खेल खेला जाता है। दवाकारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक दवा कंपनी से डीलर सीधा संपर्क करते हैं और निश्चित मात्रा में दवा सप्लाई के लिए जिलों का ठेका लेते हैं। इससे उन्हें प्रिंट रेट से 10 से 20 प्रतिशत मूल्य पर माल मिल जाता है। इसके बाद कंपनी उन जिलों में अपनी दवा की आपूर्ति नहीं करती। डीलर डाक्टरों और नर्सिंगहोम से संपर्क करके दवा की बिक्री कराते हैं। प्रिंट रेट पर चालीस से पचास फीसदी कमीशन दवा लिखने वाले को मिलता है बांकी काउंटर डीलर के ही होते हैं। एक थोक दवा कारोबारी खेल को समझाते हुए बताते कि किडनी के मरीजों के लिए मेरोपेनम साल्ट का इंजेक्शन लगता है। यह इंजेक्शन बाजार में पांच से सात सौ रुपया में मिलता है लेकिन नर्सिंगहोमों में इसी साल्ट का इंजेक्शन 2200 से 2400 रुपया तक में मिलता है। एंटीबायोटिक सिफक्जिम, सिप्रोफ्लाक्सासिन, एसलोफेनिक, मल्टीविटामिन ओमेप्राजोल, पैंटोप्राजोल आदि वह दवाएं जो सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें यह खेल खूब चलता है। यह कुछ साल्ट तो बानगी मात्र हैं। दवा व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया कि इस खेल को दवा कारोबारियों की भाषा में प्रोपेगंडा की दवा कहा जाता है। इस खेल के चलते रोगियों को वह दवा भी महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही है जो स्टैंडर्ड कंपनी की सस्ती मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि इस खेल में सभी डाक्टर और नर्सिंगहोम शामिल हों लेकिन दो तिहाई अस्पताल और तकरीबन तीस फीसद डाक्टर इस खेल में शामिल हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र राजेश बाबू कटियार ने बताया कि मोनोपोली दवाएं वह हैं जो बड़ी कम्पनियों की दवाओं के सब्स्टिटूट व साल्ट के आधार पर हर जिले में बड़े चिकित्सक व विशेषज्ञ अपने हिसाब से बनवाते (उत्पाद तैयार कराते) हैं जोकि गिनेचुने मेडिकल स्टोरों पर सेटिंग के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं जो डॉक्टर इन दवाओं को लिखता है वह उसके आसपास के लोकेशन वाले मेडिकल स्टोरों पर ही उपलब्ध होती हैं। यह दवाएं एक जिले से दूसरे जिले या अन्य मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती हैं। ये दवाएं पेटेंट एवं जेनरिक की अपेक्षा 30 से 90 गुना तक महंगी होती है। देखा जाए तो मोनोपोली दवाइयां जेनरिक दवाइयों से भी गुणवत्ता में खराब होती हैं लेकिन इस बात को मरीज या उसका तीमारदार नहीं समझते वह उसी दवा को खरीदना पसंद करते हैं जो डॉक्टर ने उनके पर्चे पर प्रीस्क्राइब्ड की है। कुछ अच्छे डॉक्टर पेटेंट दवाइयां ही लिखते हैं और कुछ मरीजों के समझदार तीमारदार मोनोपोली दवाओं की जगह उसी फार्मूले की पेटेंट दवाईयां खरीदना पसंद करते हैं। पेटेंट दवाइयां गुणवत्ता में शत प्रतिशत बेहतर साबित होती हैं और मोनोपोली दवाइयों से कम दाम पर मिलती भी हैं।

'महिलाओं के खिलाफहिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस' पर एएमयू में 16 दिवसीय कार्यक्रम शुरू

अलीगढ़, (यूएनएस)। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 'अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस' के अवसर पर आज महिलाओं के विरूध होने वाली हिंसा पर जागरूकता बढ़ाने और उनके लिए विशेष सहायता को बढ़ावा देने के उद्द्श्य से आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के तत्वाधान में 16 दिवसीय सम्मलेन के उद्घाटन सत्र में वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा कि लोग लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूक हो रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस दिशा में और अधिक करने की जरूरत है। लिंग आधारित हिंसा के मूल कारणों को समाप्त करने और दूर करने के प्रयासों में रोकथाम एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। ऐसे निरोधात्मक कार्य में युवा सक्रियता के साथ महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही चीजें धीरे-धीरे बदल रही हैं, अपने हमें नजरिए को बदलने के लिए और अधिक काम करने और समाज में लिंग आधारित हिंसा को स्वीकार्य बनाने वाली लैंगिक भूमिकाओं और रूढ़ियों पर सवाल उठाने की जरूरत है। यह अभियानों के आयोजन, प्रशिक्षण, सहकर्मी शिक्षा या जीवन के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता के आयाम को शामिल करके किया जा सकता है। प्रोफेसर मंसूर ने कहा कि यह संतोष की बात है कि दुनिया भर में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्कैंडिनेवियाई और नॉर्डिक देशों में राज्यों में महिलाएं राष्ट्र अध्यक्ष हैं और भारत में सभी आयु समूहों और पृष्ठभूमि की महिला उद्यमी लगातार रूढ़ियों को तोड़ रही हैं और व्यापार परिदृश्य को बदल रही हैं और राजनीति, सिविल सेवाओं और पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ रहा है। मानद अतिथि, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज ने कहा कि लिंग आधारित हिंसा और स्त्री द्वेष की संस्कृति महिलाओं का अवमूल्यन करती है, दुर्व्यवहार को सामान्य या इसकी तीव्रता को कम करती है, यौनवाद को नजरअंदाज करती है, आक्रामकता को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोगों से यह समझने का आग्रह किया था कि एक महिला के दिल में क्या है और महिला को 'कमजोर लिंग' नहीं कहना चाहिए क्योंकि यह एक अपमान होगा और महिलाओं के प्रति पुरुष का अन्याय होगा। इतिहास विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद ने 'महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवसः विषय, इतिहास, महत्व और मुख्य तथ्य' पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। एक महिला को उसके साथी के द्वारा टुकड़ों में काट दिया गया, एक छह साल की बच्ची को उसके पिता ने मार डाला, एक युवा लड़की को उसके माता-पिता ने मार डाला और नोएडा में एक स्थानीय मीडिया लेखक को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया या शायद एक इमारत की 16 वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। हम ऐसी क्रूर कहानियों के बारे में सुनते रहते हैं। इस से स्पष्ट है कि समाज और हमारी सामूहिक विचार प्रक्रियाओं में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि हम इन मुद्दों पर एक विश्वविद्यालय में बात कर रहे हैं जहां सार्वजनिक धन ज्ञान निर्माण और प्रसार पर खर्च किया जाता है। इस तरह के संस्थागत स्थानों पर लोगों को इस तरह के रवैये से नाराज होने के प्रति संवेदनशील बनाने और हिंसक प्रतिगामीवाद के खिलाफ एक सामूहिक सामाजिक रवैया बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रोफेसर नईमा खातून (प्रिंसिपल, महिला कॉलेज) ने 'महिलाओं के खिलाफ हिंसाः इसके प्रकार और व्यक्ति, समाज और राष्ट्र पर प्रभाव' पर बात की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा सबसे प्रबल मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। यह महिलाओं के जीवन के लिए खतरा है, यह उनके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, और यह उनके बच्चों की भलाई के लिए खतरा है, जिसका दुष्प्रभाव पूरे समुदाय पर होता है। उन्होंने कहा कि अपराधी हर सामाजिक और आर्थिक परिवेश में पाए जा सकते हैं।'महिलाओं के खिलाफहिंसाः रोकथाम और संरक्षण' पर बोलते हुए, डॉ अंबेडकर चेयर फॉर लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, कानून विभाग के डा. जफर अहमद खान ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा लिंग आधारित भेदभाव और सामाजिक मानदंडों में निहित है जो हिंसा को स्वीकार करते हैं। आज तक, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के प्रयासों ने मुख्य रूप से केवल प्रतिक्रिया देने और सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि रोकथाम के उपायों से हिंसा से जुड़े संरचनात्मक कारणों के साथ-साथ जोखिम और सुरक्षात्मक कारकों को संबोधित करना महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वागत भाषण में, आईसीसी की पीठासीन अधिकारी, प्रोफेसर सीमा हकीम ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसके अंतर्गत लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ वैश्विक 16 दिनों की सक्रियता का उद्घाटन दिन है। उन्होंने कहा कि आईसीसी, एएमयू द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम लोगों में जागरूकता बढ़ाएंगे कि लिंग आधारित हिंसा दुनिया भर में लाखों महिलाओं, लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। इस अवसर पर एक लघु एनिमेटेड फिल्म, 'जीवन चक्र के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा', महिलाओं की आंतरिक उथल-पुथल और मानसिक और शारीरिक हिंसा से निपटने के लिए विभिन्न परतों को सामने लाने वाली फिल्म भी दिखाई गई। वक्ताओं ने बाद में एक विशेष 'ओपन हाउस' इंटरैक्टिव सत्र में छात्रों के प्रश्नों के उत्तर दिये। प्रोफेसर संगीता सिंघल (सदस्य, आईसीसी) ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन सारा सुल्तान खान ने किया।

मानसिक स्वास्थ्य और कोविड-19 : चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं' विषय पर एएमयू में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

अलीगढ़, (यूएनएस)। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग द्वारा आज यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक सभागार में 'मानसिक स्वास्थ्य और कोविड 19: चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हाइब्रिड मोड और आनलाइन मोड में आयोजन किया। उद्घाटन समारोह में विशेषज्ञों ने लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड महामारी के गहरे नकारात्मक प्रभाव पर गहन विचार विमर्श किया। वाइस चांसलर, प्रोफेसर तारिक मंसूर ने मुख्या अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि महामारी से सभी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर किसी न कसी हद तक प्रभाव पड़ा है मनोवैज्ञानिकों को उनके मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए विशेष कदम उठाने कि आवश्यकता है। प्रो. मंसूर ने कहा कि विभिन्न देशों और समुदायों में चिंता, तनाव, अवसाद के स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। प्रो मंसूर ने कहा कि महामारी के बाद दुनिया चुनौतियों से भरी हुई है जिस पर ध्यान देने कि आवश्यकता है। कुलपति ने विश्वास जताया कियह सम्मेलन लोगों की तत्काल चिंता पर वैज्ञानिक विचार-विमर्श के लिए एक आवश्यक मंच प्रदान करेगा और मुद्दों के समाधान और समय पर उपचार के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने उन लोगों के मनोवैज्ञानिक आघात पर भी बात की, जो ब्लैक फंगस से पीड़ित थे और कैसे स्कूल जाने वाले छात्रों को तालाबंदी और अन्य प्रतिबंधों के दौरान अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा। मानद अतिथि, प्रोफेसर असोके कुमार साहा (जगन्नाथ विश्वविद्यालय, ढाका, बांग्लादेश) ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सक्रिय भागीदारी और वैज्ञानिक विचार-विमर्श हमें संभावित समाधान की ओर ले जाएगा, जो न केवल मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए, बल्कि सामान्य रूप से सभी के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आम जनता में अवसाद, चिंता, तनाव, पैनिक डिसऑर्डर, जुनूनी-बाध्यकारी विकार, दैहिक लक्षण, नींद की बीमारी, प्रलाप, मनोविकृति, आत्म-विकृति और आत्महत्या में वृद्धि हुई है और हमें बहुत देर होने से पहले इनका समाधान खोजना होगा।अतिथि वक्ता, प्रोफेसर मिनाती पांडा (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) ने बताया कि किस प्रकार कोविड महामारी व्यापक रुग्णता और मृत्यु दर का कारण बना, और इस ने अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामान्य रूप से लोगों और विशेष रूप से बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को सामूहिक कल्याण के समाधान को समझने और प्रदान करने का काम सौंपा गया है और यह सम्मेलन हमें दुनिया के विभिन्न कोनों से विद्वानों को सुनने और प्रत्येक के लिए शांति और कल्याण को बहाल करने के तरीके पर विचार करने का अवसर देगा। प्रोफेसर मिर्जा असमर बेग (डीन, सामाजिक विज्ञान संकाय) ने कहा या कि कोविड महामारी के बाद सभी का जीवन प्रभावित हुआ है। इसने लोगों को गंभीर मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के मुद्दों के साथ पीछे छोड़ा है। इस परिदृश्य में, यह अनिवार्य है कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और विद्वान समाधानों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएं। स्वागत भाषण में मनोविज्ञान विभाग की चेयरपर्सन प्रोफेसर असमा परवीन ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और स्नातकोत्तर छात्रों को महामारी के बाद की दुनिया में मौजूदा चुनौतियों पर जानकारी का आदान-प्रदान करने में मदद करना है। कार्यक्रम का संचालन अबीर मोहम्मद शाहिद व मोहम्मद सुहैल ने किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन में 170 से अधिक प्रतिभागी आफ्लाइन व आनलाइन मोड में शामिल हुए।

धरोहर कार्यक्रम में शिवाय बने डांसिंग स्टार

कन्नौज, (यूएनएस)। जिले में प्रतिभाओं को निखारने के लिए कन्नौज धरोहर डासिंग स्टार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां तमाम बच्चों ने प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रस्तुति देने वाले को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्थान दिया गया। डासिंग स्टारों को राज्य सरकार के मंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पीएसएम पीजी कालेज में कन्नौज धरोहर डांसिंग स्टार कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका शुभारंभ समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने दीप प्रज्जवलित कर किया। यहां शिवाय दुबे, अंकुश, शिल्पी, ईशू, अर्जुन, प्रियांशु, यशस्वी, अमन, अनुष्का, शगुन, गौरी, सुमेघा, श्रद्धा, श्रीति, उन्नति, रिद्धी, जानवी, स्नेहा, आयुषी, शिवांगी, अंशिका, शिखा, सुहानी, दृश्या, यनशीक, अंकुश, करिश्मा, मान्या, पायल समेत करीब 30 से अधिक बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भक्ति गीतों, भजनों और देशभक्ति गानों बच्चों ने डांस किए। यहां शानदार प्रस्तुति देने वाले शिवाय दुबे को प्रथम स्थान मिला। श्रद्धा त्रिपाठी को द्वितीय और पायल व करिश्मा को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान मिला। डासिंग स्टार कार्यक्रम में विजेता रहे चारो बच्चों को राज्य सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरूण ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राज्य सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरूण कन्नौज धरोहर डासिंग स्टार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अब तक जिलों में बच्चों को प्रतिभा प्रदर्शन के लिए मंच नहीं मिल पाते थे। अब उन्हें शासन-प्रशासन ने मंच उपलब्ध करवा दिया है। जिसके माध्यम से प्रतिभाओं को आगे बढने के अवसर मिलेंगे।

मैनपुरी उपचुनाव : सपा का मास्टर प्लान, ब्लाक लेबल पर प्रचार

बहू मांग रही आशीर्वाद, कहती हैं, चुनाव मेरा नही नेताजी और मैनपुरी की जनता का

लखनऊ, (यूएनएस)। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने के लिए सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। सपा प्रमुख ने विधानसभा वार चुनाव प्रचार के बाद ब्लॉक स्तर पर चुनाव प्रचार अभियान शुरु किया है। डिंपल यादव ने आज शुक्रवार को ब्लाक स्तर पर जाकर नुक्कड़ सभाएं की। मैनपुरी का रण जीतने के लिए पूर्व सांसद डिंपल यादव ने शुक्रवार को मैनपुरी के सैफई, हैंवरा, नगला बरी, परासना, नगला सेवा, टिमरुआ, नगला मठिया, परासना, समेत पूरे सैफई ब्लॉक क्षेत्र में प्रचार कर अपने लिए वोट मांगा। लोगों से मिलकर उनका हाल चाल भी जानती रही। डिंपल यादव ने कहा कि मेरी यह आप लोगों से अपील है कि यह चुनाव मेरा नहीं है यह नेता जी का चुनाव है। यह आप लोगों का चुनाव है। सैफई नेताजी का घर है और मैं आप सबकी बहू हूं। 5 दिसंबर को आप लोग भारी मात्रा में सपा के पक्ष में मतदान कर अपनी बहु को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दिलवाए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई। उनकी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में एक तरफ जहां सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी व पूर्व सांसद डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है तो वहीं भाजपा ने सपा व प्रसपा के नेता रह चुके व खुद को मुलायम सिंह यादव व शिवपाल सिंह यादव का शिष्य बताने वाले पूर्व सांसद, विधायक रघुराज शाक्य पर दांव लगाया है। बीजेपी किसी भी हाल में जीतकर सपा को तगड़ा झटका देना चाहती है।

डाबर च्यवनप्राश ने अक्षय कुमार के साथ लॉन्च किया नया कैंपेन 'घर घर बन गया दवाई की दुकान'

लखनऊ, (यूएनएस)। भारत की जानी-मानी विज्ञान आधारित आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड की ओर से दुनिया के नंबर 1 आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट ब्राण्ड डाबर च्यवनप्राश ने सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ नए कैंपेन 'घर घर बन गया दवाई की दुकान' का लॉन्च किया है। इस कैंपेन की अवधारणा मैककेन ने पेश की है, यह अभियान इस बात पर रोशनी डालता है कि आज कैसे हर घर में अपने आप दवाई लेने का ट्रेंड बन चुका है और किस तरह च्यवनप्राश अंदरूनी शक्ति बढ़ाकर 100 से अधिक बीमारियों से से लड़ने में मदद करता है। श्री प्रशांत अग्रवाल, मार्केटिंग हैड- हेल्थ सप्लीमेंट्स, डाबर इंडिया लिमिटेड ने कहा इस कैंपेन के माध्यम से हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए अपने आप को भीतर से मजबूत बनाएं, इसके बजाए अपने मन से कोई भी दवा न लें। खांसी, जुकाम और फ्लू से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी इम्युनिटी (यानि बीमारियों से लड़ने की ताकत) को मजबूत बनाएं। च्यवनप्राश ऐसा ही समाधान है जो आपको 100 से अधिक बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसमें आयुर्वेदिक 'रसायन' जड़ी-बूटियां जैसे आंवला, अश्वगंधा, गिलोय आदि होते हैं, जो इम्युनोमॉड्युलेटरी इफेक्ट के साथ कई तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं। डाबर च्यवनप्राश पिछले 100 सालों से हर भारतीय की इम्युनिटी को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है। नया टीवी विज्ञापन बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार पर फिल्माया गया है, जो दर्शकों को बताते हैं कि आजकल लोग मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए अपनी इम्युनिटी बढ़ाने के बजाए कोई भी दवा ले लेते हैं, ताकि उन्हें लक्षणों में आराम मिल लाए। यह कैंपेन इस बात पर रोशनी डालता है कि ऐसी सैंकड़ों बीमारियां हैं, जिसमें दवा लेने पर आपको अस्थायी रूप से राहत मिलती है। इसलिए लक्षणों को दबाने के बजाए अपनी इम्युनिटी बढ़ाने पर ध्यान दें। इसके लिए च्यवनप्राश बहुत फायदेमंद है जो आपकी भीतरी ताकत को बढ़ाकर 100 से अधिक बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।

सेवाभाव का अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रही है लांयस क्लब-डीएम

बलरामपुर, (यूएनएस)। जनपद में लायंस क्लब द्वारा बलरामपुर सदर के ग्राम पंचायत जोगिया खुर्द में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए राहत सामग्री वितरण कैंप का आयोजन किया गया।इस आयोजन में मुख्य अतिथि विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ला एवं विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी डॉ महेंद्र कुमार द्वारा 100 बाढ़ पीड़ितों व जरूरतमंदों को राहत सामग्री एवं दो-दो रजाई का वितरण किया गया साथ ही जिलाधिकारी ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने पर लायंस क्लब को धन्यवाद दिया और जिलाधिकारी डॉ महेंद्र कुमार ने कहा कि जनपद को भीषण बाढ़ की त्रासदी से गुजरना पड़ा। जिसमें जनपद की लगभग 5 लाख आबादी प्रभावित हुई,बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर किया गया। जिसमें कि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आगे आकर मदद की गई।लायंस क्लब द्वारा बाढ़ पीड़ितों एवं जरूरतमंदों को राहत सामग्री एवं ठंड से बचाव के लिए रजाई वितरण कर सेवाभाव का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया गया है।वही इस शिविर के दौरान बात करते हुए लायंस क्लब अध्यक्ष निष्काम गुप्ता ने बताया कि कैंप में डायबिटीज एवं मोतियाबिंद की निशुल्क जांच की जा रही है,ज्यादा से ज्यादा लोग आकर निशुल्क जांच का लाभ ले।

वही इस अवसर पर लायंस क्लब अध्यक्ष निष्काम गुप्ता, सचिव अशोक गुप्ता मंडल चीफ विश्वनाथ चौधरी, डिस्ट्रिक्ट सचिव विनीत श्रीवास्तव, रीजनल चेयरमैन प्रितपाल सिंह,ब्लड डोनेशन चेयरमैन आलोक अग्रवाल, तहसीलदार बलरामपुर सदर अवधेश कुमार व जनप्रतिनिधि गण, संबंधित अधिकारी,कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

गोंडा में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, मामला दर्ज

लखनऊ, (यूएनएस)। यूपी के गोंडा जिले के वजीरगंज थानाक्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने शुक्रवार को बताया कि पीड़िता के पिता ने कल बृहस्पतिवार को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ 19 नवंबर को गांव के ही दो युवकों ने बलात्कार किया।16 वर्षीय पीड़िता गांव के ही अपने खेत में चारा लाने गई थी और इसी दौरान आरोपियों ने उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। एएसपी ने बताया कि आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस बीच बृहस्पतिवार को एक आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। किशोरी के पिता की तहरीर के आधार पर स्थानीय पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ दुष्कर्म, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानि पॉक्सो अधिनियत व आईटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

जिला उद्योग बंधु की बैठक 30 नवंबर को

औरैया, (यूएनएस)। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र अधिकारी उत्कर्ष चन्द्र ने बताया है कि जिला उद्योग बंधु की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 30 नवंबर को मध्याह्न 12 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुख्यालय ककोर में आयोजित की जाएगी। सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि अपने विभाग की प्रगति के साथ बैठक में समय से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

लापता युवक का शव कुआं में मिला, घर में मचा कोहराम

झांसी, (यूएनएस)। जिले में करीब 24 घंटे से लापता युवक का शव कुआं में मिलने से सनसनी फैल गई। वह मानसिक रूप से कमजोर था। लापता होने के बाद पूरा परिवार उसकी तलाश में जुटे हुए थे। शव मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया। जनपद के रक्सा थाना क्षेत्र के गांव डगरवाह निवासी कल्लू (19) पुत्र जय प्रकाश राय बुधवार दोपहर को खाना खाकर घर से निकला था। फिर वह लौटकर नहीं आया। इसके बाद परिजनों ने आसपास के एरिया और रिश्तेदारियों में तलाश की। लेकिन कल्लू का कोई सुराग नहीं लग पाया। गुरुवार को ग्रामीणों ने परिजनों ने बताया कि आपके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित माता के मंदिर के पास कुआं में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे तो शव कल्लू का था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बताया कि कल्लू मानसिक रूप से कमजोर था। कल्लू तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। उससे छोटे 16 साल का राहुल और शिवम हैं। तीनों भाइयों से बड़ी शिवानी की शादी हो चुकी है। कल्लू के पिता जय प्रकाश राय खेतीबाड़ी करते हैं। मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है।

मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने के लिए आयोजित की गई कार्यशाला

कार्यशाला में बाल रोग विशेषज्ञों, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों ने लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा

न्यूज गाइड । संवाददाता

शिवगढ़, रायबरेली। रायबरेली जिले के शिवगढ़ राजमहल में स्थित कम्युनिटी एम्पावरमेंट लैब सक्षम शिवगढ़ द्वारा मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने के लिए राजधानी लखनऊ स्थित ताजमहल होटल में एक कार्यान्वयन अनुसंधान नेटवर्क की नीव स्थापित करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें बाल रोग विशेषज्ञों, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरतलब हो कि कम्युनिटी एंपावरमेंट लैब, एनएचएम एवं राज्य सरकार के समन्वित सहयोग से पिछले 19 वर्षो से नवजात शिशुओं एवं माताओं की सम्मानजनक देखभाल करती चली आ रही है। सीईएल, एनएचएम एवं राज्य सरकार के सार्थक प्रयासों से केएमसी के माध्यम से नवजात शिशु मृत्यु दर में 54 प्रतिशत कमी आई है।सीईएल की सीईओ आरती कुमार के नेतृत्व में ताज महल होटल में आयोजित इस कार्यशाला में वाराणसी,अलीगढ़, आगरा, झाँसी, कानपुर, लखनऊ मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों तथा प्राइवेट अस्पतालों के बाल रोग चिकित्सकों, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों तथा सीईएल टीम के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश था कि मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने के लिए एक ऐसा नेटवर्क स्थापित किया जाये जिसके माध्यम से कार्याशाला में आये हुए सभी प्रतिभागी एक जुट होकर महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विभिन्न प्रयासों को समाहित करके एक नयी दिशा में कार्य करें। एक रणनीति बनाये जिससे मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने में सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग को आसान बना सकें। जिसके फलस्वरूप इस कार्यशाला में आये हुए सभी प्रतिभागियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए और इन्हीं सुझाव के माध्यम से आगे चलकर एक रणनीति तैयार की जाएगी। जिसके तहत सभी प्रतिभागी एक जुट होकर काम करेंगे और मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

ब्रजेश पाठक ने सविता समाज से मांगी माफी, कहा, अनजाने में शब्द बोल गया, मैं हृदय से माफी मांगता हूं...

लखनऊ, (यूएनएस)। सूबे के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज आगरा पहुंचे और सविता समाज के लोगों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने सविता समाज के लोगों से हाथ जोड़ कर माफी मांगी। दरअसल, ब्रजेश पाठक ने सविता समाज के लोगों पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। उनका कहना है कि सविता समाज के लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनसे हृदय से माफी मंगाता हूं। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आगरा में सांसद राजकुमार चाहर के बेटों के तिलक समारोह के बाद आशीर्वाद देने पहुंचे थे। आगरा पहुंचने के बाद डिप्टी सीएम शहीद नगर स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सविता समाज के लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि सविता समाज के लोगों को भावनाओं को आहत करने का उनकी कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने समाज के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि सविता समाज के सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अनजाने में उनसे उस शब्द का प्रयोग हुआ था। वो सविता समाज के सभी लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। वो उनके हर सुख-दुख में उपस्थित रहता हूं। सभी लोगों से वो हृदय से क्षमा मांगता हैं। समाज के सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि भविष्य में उनके हर समय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहूंगा। सविता महासभा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि डिप्टी सीएम ने समाज के लोगों से माफी मांगी हैं। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाज को संदेश देने का प्रयास किया है। समाज के लोगों से मिलकर उन्होंने भरोसा दिलाया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक टीवी चौनल को दिए साक्षात्कार में सविता सेन समाज को लेकर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से सविता सेन समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। डिप्टी सीएम के खिलाफसविता सेन महासभा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की थी।

यूपी में 'पीपीपी मॉडल पर विकसित होंगे 23 बस अड्डे, यात्रियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं

लखनऊ, (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राज्य के बड़े शहरों में 23 बस अड्डों को 'पीपीपी (निजी-सार्वजनिक सहभागिता) मॉडल पर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये हवाई अड्डे की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को लोकभवन में पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मंत्री ने बताया कि लखनऊ, आगरा और प्रयागराज के दो-दो बस अड्डे तथा बनारस, कानपुर, गोरखपुर समेत बड़े शहरों के 23 बस अड्डों को हवाई अड्डे की तर्ज पर पीपीपी मॉडल से बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इसमें हर तरह की सुविधा मिलेगी और जो यात्री आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था भी रहेगी। मंत्री ने कहा कि इन बस अड्डों में अच्छे होटल और भोजनालय के इंतजाम के साथ वहां पर उन्हें सामान की खरीददारी के लिए मॉल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सिंह ने कहा कि जिस तरह हवाई अड्डों पर बेहतर शौचालय, बैठने के लिए अच्छी सुविधाएं और महिलाओं के लिए अलग सुविधाएं रहती हैं, उसी तरह पेयजल से लेकर आधुनिक सभी सुविधाएं इन बस अड्डों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन प्रथम चरण में बड़े शहरों में 23 बस अड्डों के निर्माण से इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इसकी निविदा जल्द ही जारी कर दी जाएगी।

खाद की समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन

कानपुर देहात, (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष नरेश कटियार के नेतृत्व में प्रदेश में रबी की फसल की बुवाई के लिए उर्वरक डीएपी की भारी कमी से परेशान किसानों की समस्या के तत्काल समाधान हेतु राज्यपाल को प्रेषित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसियों ने राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराने एवं किसानों की समस्या से संबंधित बिंदुओं का उल्लेख करते हुए लिखा कि प्रदेश के सभी मंडलों के विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित प्रदेश के किसानों के लिए रबी के लिए आवश्यक खाद उर्वरक डीएपी की भारी कमी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है।हालांकि प्रदेश कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री को राज्य में रबी की फसल की बुवाई के लिए डीएपी की होने वाली कमी के लिए पहले से ही अवगत कराया जा चुका है। किंतु प्रदेश सरकार और प्रशासन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं। सहकारी समितियों में गोदामों पर मात्र एक बोरी खाद पाने के लिए किसानों की लंबी कतारें लग रही है और स्थानीय स्तर पर सरकारी अधिकारीगण समस्या के शीघ्र समाधान का कोरा आस्वासन ही दे रहे हैं।उधर केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय ने दावा किया कि देश प्रदेश में चालू रबी की फसल के लिए उर्वरक का भरपूर स्टॉक है। इससे स्पष्ट है कि किसानों के लिए खाद उर्वरक डीएपी की कमी की स्थिति जानबूझकर पैदा की गई है। इसलिए किसानों के हित में कांग्रेस मांग करती है कि खाद की आपूर्ति शीघ्र कराई जाए। जिससे फसल की बुवाई समय पर की जा सके। ज्ञापन में रोहित कटियार राजकुमार सविता समीम कुरेशी आफताब जोहरी आदित्य श्रीवास्तव सगीर अहमद बसंत लाल आदर्श कटियार राजन सचान अमीर अली सुरेंद्र कटियार आदर्श सक्सेना तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी अमृत सिंह गौर ने हस्ताक्षर किए।

बंद आंगनबाड़ी केंद्र,नदारद कार्यकत्रियों का डीपीओ ने रोका मानदेय, मांगा स्पष्टीकरण

कानपुर देहात, (यूएनएस)। जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश यादव द्वारा बाल विकास परियोजना अकबरपुर शहर स्लम के केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र कालीगंज प्रथम में कार्यरत तनवीर, कालीगंज द्वितीय में कार्यरत करिश्मा, सिद्धनगर प्रथम की अनीता द्विवेदी व सिद्धनगर द्वितीय की उमाकान्ती का केंद्र बंद पाया गया। जिसके दृष्टिगत इन सभी का मानदेय रोका गया।इसी क्रम में रामगंज प्रथम में अल्का श्रीवास्तव, रामगंज द्वितीय में वाजिदा बेगम का केन्द्र तो खुला मिला पर बच्चों की संख्या कम पाई गई। इटैली की किरन बाथम,गाँधीनगर प्रथम की साधना सिंह, गाँधीनगर द्वितीय की स्नेहलता के केन्द्र मे बच्चों की संख्या शून्य पाई गई।जिसपर कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित ऑगनबाड़ी कार्यकत्रीयों का स्पष्टीकरण मांगा गया।

साक्षी यादव मिस और साहिल उद्दीन बने मिस्टर फ्रेशर्स

झांसी, (यूएनएस)। जिले के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा प्रथम वर्ष के छात्रों को फ्रेशर पार्टी दी गई। फ्रेशर पार्टी में साक्षी यादव को मिस फ्रेशर एवं साहिल उद्दीन को मिस्टर फ्रेशर चुना गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुहानी कुशवाहा ने सोलो सिंगिंग, साक्षी एवं वैष्णवी ने सोलो डांस, रिमझिम एवं स्नेहा की टीम द्वारा ग्रुप डांस किया गया। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका डॉ. अतुल गोयल एवं डॉ. गजला अहमद ने की। संचालन बीकॉम द्वितीय वर्ष की श्रद्धा वर्मा, कौशिक गुप्ता, रिमझिम साहू, रितिक कनौजिया, रोशनी सिद्दीकी ने किया। कार्यक्रम संयोजन बीकॉम फाइनल ईयर की छवि द्विवेदी, नजराना कुरेशी, चंचल कुशवाहा, विशाल साहू, अनामिका गुप्ता व अमित साहू ने प्रमुख रूप से कार्य किया। इस अवसर पर प्रो. सीबी सिंह, डॉ. फुरकान मलिक, डॉ. शिल्पा मिश्रा, डॉ. अंकिता जैस्मिन, डॉ. प्रियंका अग्रवाल, डॉ. शिविका भटनागर, डॉ. शिखा सोनी, डॉ. रजत कंबोज, डॉ. कौशल त्रिपाठी, एमकॉम के छात्र ऋतिक पटेल उपस्थित रहे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के रसायन विभाग की एमएससी केमिस्ट्री की छात्रा दीप्ति यादव को सीएसआईआर नेट की परीक्षा रसायन विषय में उत्तीर्ण करने पर कुलपति मुकेश कुमार पाण्डेय ने शुभकामनाएं दी। छात्रा ने बताया कि वह भविष्य में सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करना चाहती है। इस अवसर पर कुलसचिव विनय कुमार सिंह, विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रो. आरके सैनी, डॉ. प्रकाश चंद्र, डॉ. कमलेश बिलगंइया, डॉ. धर्मेंद्र के साथ अनेक शिक्षक उपस्थित रहे।

अभाविप के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही और राष्ट्रीय महामंत्री शुक्ल ने संभाला दायित्व

एजेंसी

जयपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही और नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने जयपुर में शुरू हुए तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन अपना दायित्व ग्रहण किया। एबीवीपी अध्यक्ष एवं महामंत्री चुनाव के निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. सुब्बैया ने इससे पहले, राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय महामंत्री के निर्वाचन संबंधी जानकारियां प्रतिनिधियों से साझा कीं। एबीवीपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही मूलतः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हैं। उन्होंने शिक्षाशास्त्र में पीएचडी की उपाधि हासिल की। वर्तमान में डॉ. शाही बाबासाहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में शिक्षाशास्त्र विभाग में सह-आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। वे प्रतिष्ठित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में एसोसिएट रहे हैं। वर्ष 2017 में श्रेष्ठतम शिक्षक सम्मान योगीराज बाबा गंभीरनाथ स्वर्ण पदक से डॉ. शाही को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया था। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल मूलतः झारखंड के गढ़वा जिले से हैं। याज्ञवल्क्य शुक्ल की शिक्षा रांची से भूगोल विषय में पीएचडी तक हुई है। वे जगजीत सिंह नामधारी महाविद्यालय, गढ़वा के निर्वाचित छात्रसंघ अध्यक्ष तथा रांची विश्वविद्यालय के निर्वाचित छात्रसंघ उपाध्यक्ष रहे हैं। पूर्व में याज्ञवल्क्य शुक्ल ने रांची महानगर संगठन मंत्री, झारखंड प्रांत संगठन मंत्री तथा केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शाही ने दायित्व ग्रहण करने के बाद कहा कि एबीवीपी की ध्येय यात्रा निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। यहां न दायित्व का दबाव है, न दायित्व का प्रभाव है। यह एक ध्येय यात्री का सहज स्वभाव है। एबीवीपी की यात्रा त्याग और विचार स्वातंत्र्य के साथ गतिशील है। हम समरसता तथा एकता के भाव को लेकर एबीवीपी के छात्र आंदोलन में आगे बढ़ेंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि एबीवीपी सतत प्रवाहमान संगठन है। एबीवीपी में मुझ जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय महामंत्री बन सकता है। संघर्ष, सेवा एवं संकल्प की परंपरा को वे आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। एबीवीपी के जिन कार्यकर्ताओं ने संगठन को आज की स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया, उनको नमन।

इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई: पीटीआई

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि इस्लामाबाद प्रशासन ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ एक विरोध रैली को संबोधित करने के लिए शनिवार को रावलपिंडी के परेड ग्राउंड पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। खान के 26 नवंबर को रावलपिंडी में अपने समर्थकों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी में उनकी पार्टी का विरोध ''पूरी तरह से शांतिपूर्ण'' होगा। पीटीआई नेता असद उमर ने ट्विटर पर कहा कि इस्लामाबाद प्रशासन ने पार्टी अध्यक्ष के हेलीकॉप्टर को शनिवार को परेड ग्राउंड पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पीटीआई' की वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिरीन मजारी ने भी परेड ग्राउंड पर खान के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं देने के लिए इस्लामाबाद प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र (आईसीटी) प्रशासन के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, ''साजिशकर्ताओं के मन में इमरान खान का डर घुस गया है।'' इस सप्ताह की शुरुआत में, 'पीटीआई' ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में एक याचिका दायर कर खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड पर उतरने और उड़ान भरने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि उसे खान के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति देने संबंधी 'पीटीआई' के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान सेना के मुख्यालय की ओर से जारी एक बयान के हवाले से 'डॉन' समाचार पत्र ने अपनी खबर में कहा, ''अधिकारियों द्वारा मंजूरी के अधीन हेलीकॉप्टर को उतारे जाने संबंधी अनुरोध पर सेना मुख्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।'' गौरतलब है कि खान (70) तीन नवंबर को पूर्वी शहर वजीराबाद में विरोध मार्च निकालने के दौरान अपने काफिले पर हुए हमले में बाल-बाल बच गये थे। हमला उस समय हुआ था जब खान मार्च का नेतृत्व कर रहे थे, जिसका समापन राजधानी इस्लामाबाद में होना था।

एक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य, दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है: प्रह्लाद जोशी

एजेंसी

नई दिल्ली। संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी को समान अवसर सहित मूलभूत अधिकार सुनिश्चित करने में भारत के संविधान के महत्व को रेखांकित करते हुए शुक्रवार को कहा कि एक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। जोशी ने 26 नवंबर को मनाये जाने वाले संविधान दिवस को समर्पित दो पोर्टल के नये एवं उन्नत रूप को डिजिटल माध्यम से लोकार्पण करते हुए यह बात कही। इसमें पहला पोर्टल ऑनलाइन माध्यम से संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से संबंधित है और दूसरा 'ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता' से संबंधित है जिसे संसदीय मामलों के मंत्रालय ने तैयार किया है। संसदीय मामलों के मंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर वर्ष 2015 से इस महत्वपूर्ण दिन को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अवसर जैसे अधिकार इस संविधान के कारण ही मिल पाए हैं।जोशी ने कहा, '' हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि एक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। अगर हम अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से पूरा करेंगे तो लोगों के अधिकार सुनिश्चित होंगे।'' उन्होंने कहा कि संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिये दो डिजिटल पोर्टल को नये एवं उन्नत रूप में तैयार किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि संविधान की प्रस्तावना को ऑनलाइन माध्यम से 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में पढ़ने की व्यवस्था की गई है। इस पोर्टल पर कोई भी पंजीकरण करा सकता है और इन भाषाओं में से किसी में भी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी पोर्टल को भी नये रूप में पेश किया गया है। यह जनभागीदारी के उद्देश्य के साथ एक सरल डिजिटल प्रश्नोत्तरी है, जिसमें भारतीय संविधान, उसमें निहित मौलिक कर्तव्यों के विशेष संदर्भ में, और लोकतंत्र पर बहुत ही सरल और बुनियादी प्रश्न शामिल हैं। कोई भी इस प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकता है और अपना नाम, टेलीफोन नंबर, आयु समूह देते हुए सामान्य रजिस्ट्रेशन के साथ प्रतिभागिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। गौरतलब है कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। संविधान दिवस की शुरुआत 2015 से की गई थी।

कोविड-19: संक्रमण के 347 नए मामले, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 5,516 हुई

एजेंसी

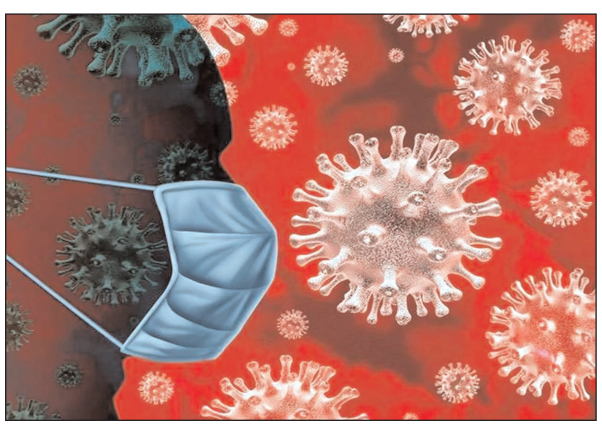

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 347 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,70,830 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 5,516 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में संक्रमण से दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक में एक-एक मरीज की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,30,604 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 5,516 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.01 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 365 की कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.80 प्रतिशत है। देश में अभी तक कुल 4,41,34,710 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 219.89 खुराक दी जा चुकी हैं। गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार हो गए थे।

स्कूल कक्षा घोटाला: सतर्कता निदेशालय ने की विशेष एजेंसी से जांच की सिफारिश

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय (डीओवी) ने 193 स्कूलों में 2,405 कक्षाओं के निर्माण में कथित श्अनियमितता और भ्रष्टाचारश् के एक मामले में अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप जांच की सिफारिश की है। शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी की जांच-पड़ताल के बाद तैयार की गई डीओवी रिपोर्ट प्रथमदृष्ट्या एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करती है। मामले में एक विशेष एजेंसी द्वारा जांच का सुझाव दिया है। डीओवी ने इस साल 22 अगस्त को की गई एक शिकायत के बाद मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की 17 फरवरी, 2020 की रिपोर्ट के संबंध में दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया गया है। सीवीसी ने मामले पर टिप्पणी के लिए डीओवी को रिपोर्ट भेजी थी। सतर्कता विभाग ने शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय करने की भी सिफारिश की है, जो लगभग 1,300 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे। शुक्रवार को एक सूत्र ने बताया कि इसने पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग के जवाबों के साथ अपने निष्कर्षों को सीवीसी को विचार के लिए भेजने की भी सिफारिश की है।निविदा प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कई प्रक्रियात्मक खामियों, नियमों के उल्लंघन के अलावा डीओवी ने अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से निजी व्यक्तियों की भूमिका को रेखांकित किया है। मैसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स ने अवैध रूप से न केवल 21 जून, 2016 को तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री के कक्ष में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया, बल्कि पोस्ट-टेंडर के लिए मंत्री को भी प्रभावित किया। रिपोर्ट में सचिव (सतर्कता) ने लिखा है कि गैर संवैधानिक एजेंसियांध्व्यक्ति (जैसे मैसर्स बब्बर और बब्बर एसोसिएट्स) प्रशासन चला रहे थे और नियम व शर्तें निर्धारित कर रहे थे। इस तरह के ष्टिकोण से प्रशासनिक अराजकता पैदा होगी।

गांधी की भूमि पर, कंधाल जडेजा अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं

एजेंसी

कुटियाना। निवर्तमान विधायक कंधाल जडेजा ने लोगों से उन्हें फिर से निर्वाचित करने की अपील करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नरेन्द्र मोदी के नाम पर वोट मांगती है लेकिन ''क्या आप अपने गांव के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को फोन करेंगे।'' उन्होंने स्थानीय स्तर पर काम करने के लिए उन्हें चुनने को कहा ताकि उन्हें (मतदाताओं) दिल्ली पर निर्भर नहीं होना पड़े। गुजरात में लोगों के बीच यह चर्चा आम है कि गुजरात में अगली सरकार कौन बनायेगा लेकिन साथ ही यह भी चर्चा का विषय है कि 'भाई' (जडेजा) इस ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अपना राजनीतिक प्रभुत्व बरकरार रख पायेंगे या नहीं। जडेजा को अक्सर 'भाई' के रूप में संदर्भित किया जाता है। जडेजा संतोकबेन जडेजा के बेटे हैं। संतोकबेन के जीवन पर एक फिल्म 'गॉडमदर' भी बनी थी। कंधाल जडेजा कई गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी हैं लेकिन उनका दावा है कि ये मामले अतीत से संबंधित हैं और लोग उनकी पहुंच और काम के कारण उन्हें वोट देते हैं। जब उनसे उनके खिलाफ डराने-धमकाने के आरोप के बारे में पूछा गया तो जडेजा ने अपने आसपास लोगों की भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह 'ताकत का जोड़' नहीं है, बल्कि 'एकता का जोड़' है। उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टियां उनका विरोध करती हैं क्योंकि वह लोगों के दिलों में 'जीते' हैं। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी मदद करने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के वास्ते उनकी तत्परता के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कई लोग यह भी स्वीकार करते हैं कि वह किसी भी विरोध को हल्के में नहीं लेते हैं। कुटियाना गुजरात के पोरबंदर जिले का हिस्सा है। पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्मस्थान है। आरोप है कि जडेजा के माता-पिता एक आपराधिक गिरोह चलाते थे, लेकिन बाद में गिरोह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर इस गिरोह को कमजोर कर दिया था। पोरबंदर, हालांकि, जिले में एक अलग विधानसभा क्षेत्र है। उनके पिता सरमन मुंजा जडेजा को प्रतिद्वंद्वियों ने गोली मार दी थी। उनकी मां 1990 में कुटियाना से विधायक चुनी गई थीं। कंधाल जडेजा ने 2012 और 2017 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के टिकट पर पोरबंदर की कुटियाना सीट से चुनाव जीता था लेकिन इस बार कांग्रेस-राकांपा गठबंधन में यह सीट राकांपा को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिली है। टिकट नहीं मिलने पर कंधाल जडेजा ने राकांपा से इस्तीफा दे दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि 'कंधाल भाई' काम करने में विश्वास करते हैं और इसके तौर-तरीकों से ज्यादा चिंतित नहीं हैं। कंधाल जडेजा का कहना है ''काम के लिए थोड़ा इधर उधर करता हूं। काम है तो नाम है।'' उनका कहना है इसीलिए वह भाजपा या कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों में शामिल नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, ''बड़ी पार्टियों में आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन मैं नियमों का पालन करने में नहीं बल्कि अपना काम करवाने में विश्वास करता हूं। कांग्रेस के कई स्थानीय कार्यकर्ता उनका समर्थन कर रहे हैं ताकि जडेजा की जीत से भाजपा की एक सीट कम हो सके। जडेजा खुद को भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई से दूर रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ''मेरा ध्यान सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के 'विकास' पर है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कहीं और क्या हो रहा है।

देश-विदेश डायरी

चीन के राष्ट्रपति शी ने मूल हितों पर क्यूबा का समर्थन करने का संकल्प लिया

बीजिंग, एजेंसी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और उनके क्यूबाई समकक्ष ने एक-दूसरे के कम्युनिस्ट देशों के ''मूल हितों'' का परस्पर समर्थन करने का संकल्प लिया है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेल बर्मुडेज से शी ने कहा है कि चीन क्यूबा के अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में समन्वय व सहयोग मजबूत करने की उम्मीद करता है। चीन सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति में शी के हवाले से कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे की विशेषताओं के साथ समाजवाद के रास्ते पर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।चीन आमतौर पर मूल हितों को अपने दावे वाले क्षेत्रों, खासतौर पर ताईवान पर नियंत्रण के अलावा देश के आर्थिक एवं राजनीतिक विकास लक्ष्यों के रूप में परिभाषित करता है। हालांकि, चीन सरकार की विज्ञप्ति में कोई विशेष मुद्दा या अन्य देश का उल्लेख नहीं किया गया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागीन खुरेलसुख और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के अगले हफ्ते बीजिंग की यात्रा करने का कार्यक्रम है।

पश्चिमोत्तर चीन में शिनजियांग के एक अपार्टमेंट में आग लगने से 10 लोगों की मौत, नौ घायल

बीजिंग, एजेंसी। पश्चिमोत्तर चीन के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र की एक आवासीय इमारत में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मध्य चीन में कुछ दिन पहले ही आग लगने की घटना में 38 लोगों की मौत हो गई थी। शिनजियांग की राजधानी उरुमची में स्थित अपार्टमेंट में बृहस्पतिवार रात को आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि आग को बुझाने में तीन घंटे का समय लगा। उन्होंने बताया कि इमारत में आग लगने के कारण 10 लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि इस घटना में घायल हुए किसी व्यक्ति की जान को खतरा नहीं है। सरकारी 'सीजीटीएन टीवी' ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इमारत के एक शयनकक्ष में बिजली के तार संबंधी किसी दिक्कत के कारण आग लगी। इससे कुछ दिन पहले मध्य चीन की एक वाणिज्य एवं व्यापार कंपनी में आग लगने से 38 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया था। चीन में पुराने होते बुनियादी ढांचे, खराब सुरक्षा प्रबंध और कुछ मामलों में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के कारण इमारतों में आग लगने की घटनाएं काफी आम हो गई हैं।

चूहों पर किए गए नए अध्ययन से फ्लू का सार्वभौमिक टीका विकसित होने की संभावना बढ़ी

वाशिंगटन, एजेंसी। वैज्ञानिकों ने इन्फ्लूएंजा 'ए' और 'बी' वायरस के ज्ञात 20 उप-स्वरूपों के 'एंटीजन' से युक्त एक नया टीका विकसित किया है, जो फ्लू के सार्वभौमिक टीकों का आधार बन सकता है। एक अध्ययन से यह जानकारी मिली है। इस टीके को अमेरिका और कनाडा के अनुसंधानकर्ताओं ने विकसित किया है। अध्ययन के अनुसार टीके के कारण चूहों और अन्य जीवों में एंटीबॉडी का निर्माण हुआ। इसमें कहा गया है कि यह टीका जीवों को बीमारी के लक्षणों और संक्रमण के बाद होने वाली मौत से बचा सकता है। अध्ययन के अनुसार, व्यापक वैश्विक निगरानी के बावजूद, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि फ्लू का कौन सा स्वरूप अगली फ्लू महामारी का कारण बनेगा। इसलिए एक सार्वभौमिक टीका का विकास अहम है।

साइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पिछले प्रयासों से भिन्न तरीका अपनाया और हर उप-स्वरूप के 'एंटीजन' को प्रक्रिया में शामिल किया। अध्ययन के अनुसार चूहों के टीकाकरण के चार महीने बाद भी उनमें एंटीबॉडी का स्तर लगभग स्थिर रहा।

चीनी-कनाडाई पॉप सितारे क्रिस वू को 13 साल की सजा

बीजिंग, एजेंसी। चीन की एक अदालत ने चीनी-कनाडाई पॉप सितारे क्रिस वू को बलात्कार समेत अन्य आरोपों के मामले में शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 13 साल कैद की सजा सुनाई। बीजिंग के चाओयांग जिला न्यायालय ने कहा कि क्रिस वू को 2020 के बलात्कार के मामले में 11 साल और छह महीने की सजा दी गई। जबकि ''यौन स्वच्छंदता में संलग्न होने के लिए भीड़ इकट्ठा करने के अपराध'' के लिए एक वर्ष और 10 महीने की सजा सुनाई गई। यह मामला 2018 का है, जिसमें क्रिस और अन्य लोगों ने कथित तौर पर दो महिलाओं का यौन शोषण किया। अदालत ने कहा कि बलात्कार के मामले में तीनों पीड़ितों ने भी शराब पी रखी थी और विरोध करने में असमर्थ थीं। इसमें कहा गया है कि संयुक्त रूप से 13 साल की सजा पर सहमति बनी है और क्रिस वू को जेल में सजा का अपना समय पूरा करने के बाद तुरंत निर्वासित कर दिया जाएगा। अदालत की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया, '' तथ्यों के अनुसार, अपराध की प्रकृति, परिस्थितियों और हानिकारक परिणामों के अनुसार, अदालत ने उपरोक्त निर्णय दिया है। एक कनाडाई राजनयिक सजा सुनने के लिए अदालत में मौजूद थे।

नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन बहुमत की ओरय नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस (एनसी) नीत सत्तारूढ़ गठबंधन संसदीय चुनाव में स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है। पांच दलों के इस गठबंधन ने शुक्रवार को अब तक घोषित 124 सीट के नतीजों में से 67 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। संघीय संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 का चयन प्रत्यक्ष मतदान के जरिये होगा, जबकि बाकी 110 को आनुपातिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुना जाएगा। किसी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए 138 सीट की आवश्यकता है। अकेले नेपाली कांग्रेस ने प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत अब तक 42 सीट पर जीत दर्ज कर ली है और वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं, उसके गठबंधन सहयोगियों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (सीपीएन)-माओइस्ट सेंटर ने 12, सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट ने 10, लोकतांत्रिक समाजवादी ने दो और राष्ट्रीय जनमोर्चा ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। ये सभी दल सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले मुख्य विपक्षी दल सीपीएन-यूएमएल (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-यूनिफाइड मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) नीत गठबंधन ने अब तक 38 सीट पर जीत दर्ज की है। सीपीएन-यूएमएल ने 30 सीट, उसके सहयोगी दलों राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी ने क्रमशरू पांच और तीन सीट पर जीत दर्ज की है। नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने सात सीट पर जीत हासिल की है। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ने दो और जनमोर्चा एवं नेपाल मजदूर किसान पार्टी ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की है। पांच सीट निर्दलीय एवं अन्य ने जीती हैं। नेपाल में संघीय संसद की 275 सीट और सात प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीट के लिए रविवार को मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार को शुरू की गई। संघीय संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 का चयन प्रत्यक्ष मतदान के जरिये होगा, जबकि बाकी 110 को 'आनुपातिक चुनाव प्रणाली' के माध्यम से चुना जाएगा। इसी तरह, प्रांतीय विधानसभाओं के कुल 550 सदस्यों में से 330 का चयन प्रत्यक्ष मतदान, जबकि 220 का चयन आनुपातिक प्रणाली से होगा।

भारत दो साल के लिए आईईसी का उपाध्यक्ष, एसएमबी का अध्यक्ष बना

नई दिल्ली, एजेंसी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत को 2023-25 कार्यकाल के लिए 'इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन' (आईईसी)' का उपाध्यक्ष और 'स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड' (एसएमबी) का अध्यक्ष चुना गया है। आईईसी सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाला निकाय है जबकि एसएमबी प्रौद्योगिकी नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार आईईसी का शीर्ष संचालनक निकाय है। इसमें बताया गया कि भारत के प्रतिनिधि विमल महेंद्रू को आईईसी का उपाध्यक्ष चुना गया है। वह आईईसी की भारतीय राष्ट्रीय समिति तथा भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न तकनीकी समितियों के सदस्य हैं। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित आईईसी की आम सभा में हुए मतदान में महेंद्रू के पक्ष में 90 फीसदी से अधिक मत पड़े।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक विद्यावती दूबे द्वारा बी डी प्रिन्टींग प्रेस गणेशपुर, रहमानपुर निकट रघुनन्दन आशियाना फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ से मुद्रित तथा- C 3/76, विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ से प्रकाशित । मो0 9450615356, फोन नं. 0522- 4102634

क्या सच में वरुण धवन के घर गूंजने वाली है किलकारियां? एक्टर ने किया ये बड़ा खुलासा

बॉलीवुड के मोस्ट एनर्जेटिक और हैंडसम हंक कहे जाने वाले वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म भेड़िया को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक्टर की ये फिल्म आज ही यानी 25 नवंबर को परदे पर रिलीज हो रही हैं। वही फिल्म के शुरूआती रुझान काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिल्म के साथ ही वरुण के पर्सनल लाइफ और वरुण के पापा बनने की खबर भी सामने आ रही है। जिसको लेकर अब वरुण धवन ने खुद अपनी चुप्पी तोड़ दी हैं। दरअसल उड़ती-उड़ती खबरे ऐसी सामने आ रही हैं की वरुण धवन के घर जल्द की किलकारियां गूंजने वाली हैं। यानी की वरुण की पत्नी नताशा दलाल प्रेग्नेंट हैं। वही जब इस खबर के बारे में वरुण धवन से पूछा गया तो उन्होंने इसे झूठ बताते हुए कहा की नताशा दलाल प्रेगनेंट नहीं है और अभी वो और उनकी वाइफ एक बेबी डॉग के पेरेंट्स हैं। इसके बाद एक्टर ने जानकारी दी कि आगे आने वाले कुछ सालों में वो माता-पिता बन सकते हैं। इसके साथ ही एक मीडिया ग्रुप को दिए हालिया इंटरव्यू में वरुण ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया हैं। जहां वरुण ने बताया की शादी के पहले बचपन में उन्होंने ये सोचा था की वो लाइफ में कभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन जब वो अपनी वाइफ नताशा दलाल से मिले उसके बाद उन्हें लगा कि यही वो लड़की है जो उन्हें हर हाल में समझ सकती है क्यों की वरुण के लिए हमेशा से शादी का मतलब अंडरस्थैंडिंग रहा था। और नताशा इसपर बखूबी खरी उत्तरी हैं। वही वरुण की फिल्म भेड़िया आज ही परदे पर रिलीज हुई हैं। और फिल्म को ठीक-थक रिस्पांस मिलते हुए भी देखा जा रहा हैं। ये कहानी है वरुण धवन की जो अरुणाचल प्रदेश जाते हैं। उन्हें एक प्रोजेक्ट पूरा करना है जिसके लिए जंगल काटने हैं। लेकिन स्टोरी यही बदल जाती हैं। जब वरुण खुद ही एक जानवर से कटवा लेते हैं। और ये जानवर कोई और नहीं बल्कि भेड़िया होता हैं। और यही से शुरू होती हैं मूवी की पूरी स्टोरी। फिल्म में वरुण के साथ कृति सेनन,अभिषेक बनर्जी, दीपक दोब्रियल भी मुख्य भूमिका में हैं। और इस फिल्म को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया हैं।

वजन कम करने के लिए नाश्ते में शामिल करें पोहा, जाने इसे खाने के अनेक फायदे

हेल्दी डाइट की बात करें तो सुबह का नाश्ता खास महत्त्व रखता है। कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता भर पेट करना चाहिए। नाश्ते में लोग जहां ब्रेड-बटर, पकौड़े, सैंडविच खाना चाहते हैं तो कभी-कभी पोहा को भी नाश्ते में शामिल कर लेते हैं। जबकि नाश्ते में पोहा रोजाना न सही पर कम से कम सप्ताह में दो -चार बार तो खाना ही चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो बता दें कि पोहा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसको खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं, आइए जानते हैं कि नाश्ते में पोहा क्यों खाना चाहिए।

एनर्जी मिलती है

सुबह के नाश्ते में पोहा खाने से बॉडी को एनर्जी मिलती है जो आपको एक्टिव रखने में मदद करती है। पोहे में काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है जो बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। इससे आपका पेट भी काफी देर तक भरा रहता है।

आयरन की कमी पूरी होती है

नाश्ते में पोहा खाने से शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है.जिन लोगों के शरीर में खून कम बनता है उनको नाश्ते में पोहा शामिल करना चाहिए। दरअसल पोहा में आयरन के गुण पाए जाते हैं। जो शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं।

घटाता है वजन

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो पोहा खाएं, इससे आसानी से वजन कम हो सकता है। इसमें मिलने वाला फाइबर आपको लंबे समय तक भूख का अहसास नहीं होने देते और इससे पेट भरा-भरा लगता है।

गैस-अपच की दिक्कत नहीं होती

ऑयली नाश्ता करने से अकसर पेट में अपच-गैस की दिक्कत हो जाती है। जबकि सुबह के नाश्ते में पोहा को शामिल करने से पाचन, गैस और अपच जैसी दिक्कत नहीं होती है। साथ ही कब्ज की दिक्कत भी कम होने लगती है। इसको खाने से पेट में भारीपन भी नहीं लगता है।

ब्लड शुगर कंट्रोल रहता

पोहा में हाई फाइबर और आयरन पाया जाता है। इसके सेवन से ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबिटीज के मरीजों के लिए पोहा एक बेहतर नाश्ता हो सकता है। **-एजेंसी**

सिर्फ पेट ही नहीं बालों के लिए भी फायदेमंद है कच्ची सब्जियां, ऐसे करें डाइट में शामिल

सब्जियां हमेशा से ही सेहत के लिए एक बेस्ट आहार माना जाता है। आजकल ऐसी हजारों सब्जियां हैं, जिन्हें पकाकर या फिर उबालकर हम सब खाना पंसद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कच्ची सब्जियां खाने के भी कई बेहतरीन फायदे हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर में पानी और पोषक तत्वों की कमी के साथ-साथ अन्य चीजों के लिए भी फायदेमंद है। आईए जानते हैं कच्ची सब्जियों को खाने के फायदे।

मिलती है एनर्जी

कार्बोहाइड्रेट के गुणों से भरपूर होने के कारण कच्ची सब्जियों का सेवन करने से आपके शरीर को उर्जा मिलती है। आप इन्हें सलाद के तौर पर खा सकते हैं।

पेट के लिए है फायदेमंद

कच्ची सब्जियों को डाइट में शामिल करने से आपका पेट हेल्दी रहता है। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिससे कब्ज, अपच और गैस की दिक्कत नहीं होती।

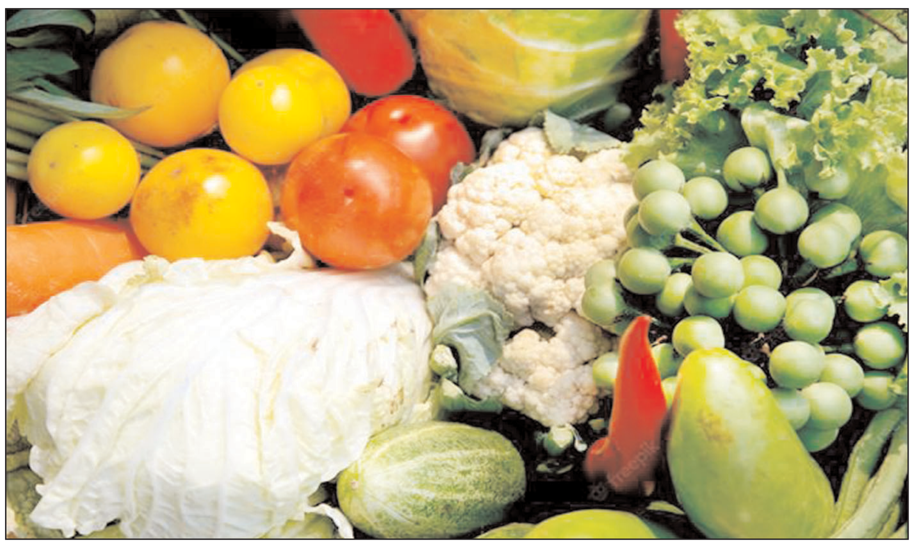

ग्लोइंग स्किन

विटामिन ए और सी के गुण से भरपूर होने के कारण कच्ची सब्जियां आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। इनके सेवन से कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। यह आपकी त्वचा में निखार लाती है।

मजबूत बाल

कच्ची सब्जियां में विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम सहित कई अन्य जरुरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनका सेवन करने से बालों का विकास बेहतर ढंग से होता है और हयरफॉल भी कम होता है।

वेट लॉस करे

अगर आप भी वजन घटाने की सोच रहे हैं, तो कच्ची सब्जियां खाना शुरु करें। इनका सेवन करने से बॉडी में फैट नहीं जमता।

एनीमिया से बचाव

अगर आप पालक का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद आयरन आपको एनीमिया से राहत दिलाता है. कच्ची सब्जियां मांसपेशियों, मस्तिष्क और बालों के लिए भी गुणकारी होती है।

ऐसे करें कच्ची सब्जियों का सेवन

आप ब्रोकली, कच्चे केले, पालक, चुकंदर, पपीता जैसी सब्जियों को कच्चा खा सकते हैं। इन्हें स्मूदी, सलाद और चाट के रुप में खाया जा सकता हैं।

वहीं अगर आप चाहें तो इनके सेवन से पहले एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं।**-एजेंसी**

वरुण धवन ने भेड़िया बनकर ये क्या कर दिया, लोगों को अब थिएटर में जाने से लग सकता है डर

वरुण धवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म आखिरकार आज यानी 25 नवम्बर को परदे पर रिलीज हो चुकी हैं। ऐसे में आज हम आपके सामने मूवी की पूरी रिव्यु लेकर आए है की आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये कहानी है वरुण धवन की जो अरुणाचल प्रदेश जाते हैं। उन्हें एक प्रोजेक्ट पूरा करना है जिसके लिए जंगल काटने हैं। लेकिन स्टोरी यही बदल जाती हैं। जब वरुण खुद ही एक जानवर से कटवा लेते हैं। और ये जानवर कोई और नहीं बल्कि भेड़िया होता हैं। और यही से शुरू होती हैं मूवी की पूरी स्टोरी। फिल्म के स्टार कास्ट की पहले बात करे तो फिल्म में वरुण धवन भास्कर शर्मा के किरदार में नजर आएँगे। वही कृति सेनन इस फिल्म में जानवरों का डॉक्टर रहती हैं जो श्अनिका मित्तल का रोल निभा रही हैं। वही फिल्म में कॉमेडी कला तड़का देते हुए अभिषेक बनर्जी जो वरुण धवन के दोस्त बनकर गुड्डू गुप्ता की भूमिका निभा रहे हैं। वही फिल्म में दीपक दोब्रियल भी हैं जिन्हे फिल्म में पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा हैं। वो इस फिल्म में राजू मिश्रा की भूमिका निभा रहे है जो जंगल वासी ही रहते हैं। वही फिल्म के सरे स्टार कास्ट बखूबी अपने किरदारों को निभाया हैं। वरुण धवन जो की अपने किरदार में काफी एनर्जेटिक और दमदार दिख रहे हैं। वरुण ने कॉमेडी और रोमांटिक से हटकर कुछ अलग जॉनर की फिल्म तरह की और फिल्म में वो इस फिल्म में काफी अच्छा कम बैक भी किए हैं। वही फिल्म में जब अभिषेक बनर्जी हैं तो सोमदत का तड़का कैसे नहीं लग सकता। जी हाँ इस मूवी में भी फुल कॉमेडी एलिमेंट अभिषेक ने ही डाला हैं। और एक तरह से कहे तो वो इस फिल्म में बैक बोन की तरह नजर आ रहे हैं। वही फिल्म की स्टोरी सहित फिल्म के ग्राफिक्स काफी दमदार हैं। फिल्म को 3क् में रिलीज किया जाएगा। और फिल्म में जितने भी विजुअल्स और सीन्स दिखाए गए हैं सभी रोंगटे खड़े कर देने वाला हैं। फिल्म में अरुणाचल की खूबसूरत लोकेशन्स भी देखने को मिलेंगी और आपका मन करेगा कि अरुणाचल जाएं। फिल्म ये मैसेज भी देती है कि जंगल बहुत जरूरी है और हमें उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और ये मैसेज बड़े एंटरटेनिंग तरीके से दिया जाता है।फिल्म का म्यूजिक फिल्म की पेस के हिसाब से फिट बैठता है. कहानी को आगे बढ़ाता है और आप गानों को एन्जॉय करते हैं. सचिन जिगर ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया है। अमर कौशिक की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म काफी दमदार और काफी इम्पैक्टफुल मैसेज देता हैं। और कही न कही बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में आनी चाहिए जो लोगों को जागरूक कर सके। तो अगर आप ये फिल्म थिएटर में जाकर देखने की सोच रहे हैं। तो आप बिल्कल जा सकते हैं। ये फिल्म पैसा वसूल फिल्म हैं।

रणबीर-आलिया ने किया बेटी के नाम का एलान, बॉलीवुड सितारों ने दी प्रतिक्रिया

रणबीर और आलिया इन दिनों अपने पेरेंट्सहुड को एन्जॉय कर रहे हैं। आलिया ने 6 नवंबर को एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया हैं। जिसकी एक झलक पाने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। वही पेरेंट्स बनने के बाद पहली बार आलिया और रणबीर ने अपनी बेटी की एक पिक्चर शेयर की हैं। साथ ही अपनी बेटी के नाम भी अब आलिया और रणबीर ने पर्दा हटा दिया हैं। दरअसल देर शाम आलिया ने अपने इंस्टग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया हैं। मां बनने के करीब 17 दिन बाद आलिया भट्ट ने एक फैमिली फोटो शेयर की है। इस फोटो में रणबीर ने अपनी लाड़ली को गोद में लिए हुए हैं। हालांकि इनकी ये फॅमिली पिक्चर पूरी तरह से साफ नहीं हैं और ये ब्लर जैसी ही दिखाई दे रही हैं। साथ ही इस दौरान दोनों ने अपनी बेटी के नाम का भी खुलासा किया है।

आलिया भट्ट-रणबीर कपूर अपनी लिटिल प्रिंसेस का नाम राहा कपूर रखा है। इसके साथ ही आलिया ने पोस्ट में ये भी बताया की उनकी प्रिंसेस का ये नाम उनकी चालाक और वंडरफुल दादी ने रखा हैं। साथ ही आलिया ने अपने बेटी के नाम का ढेरो मतलब भी बताया हैं। जहां आलिया ने लिखा है की राहा का असल में मतलब दिव्य पथ.. स्वाहिली में इसका मतलब खुश है... संस्कृत में राहा का मतलब- एक वंश बढ़ाने वाला है.. बंगाली में राहा का मतलब- आराम, कम्फर्ट, राहत, है.. तो वहीं अरबी में इसका मतलब शांति है... इस नाम का मीनिंग खुशी, स्वतंत्रता और आनंद भी है। आखिर में एक्ट्रेस ने लिखा-थैंक यू राहा, हमारी फैमिली में जान डालने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी लाइफ अभी-अभी शुरू हुई हो। वही आलिया के अब इस पोस्ट पर उनके फैंस सहित कई बॉलीवुड सेलेब्स भी कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनमे नीतू कपूर, सोनी राजदान, श्वेता बच्चन नंदा और करीना कपूर सहित कपूर परिवार के कई परिवार के सदस्यों ने शुभकामना दी है। वही करीना ने कमेंट करते हुए लिखा है की- राहा कपूर क्या मैं आपको गोद में ले सकती हूं...अब इंतजार नहीं हो रहा है।वहीं प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, गॉड ब्लेस राहा साथ में दिल वाली इमोजी भी पोस्ट की है। आलिया भट्ट की पोस्ट को अभिनेता दीपिका पादुकोण , रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा और विक्की कौशल ने भी पसंद किया।**-एजेंसी**

हमारा संविधान और भारतीय जीवन दर्शन

(संविधान दिवस/26नवंबर विशेष-)

किसी भी देश के लिए एक विधान की आवश्यकता होती है। देश के विधान को संविधान कहा जाता है। यह अधिनियमों का संग्रह है। भारत के संविधान को विश्व का सबसे लम्बा लिखित विधान होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय संविधान हमारे देश की आत्मा है। इसका देश से वही संबंध है, जो आत्मा का शरीर से होता है। भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ था। चूंकि डॉ. भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए भारत सरकार द्वारा उनकी 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को प्रथम बार संविधान दिवस संपूर्ण देश में मनाया गया। उसके पश्चात 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाने लगा। इससे पूर्व इसे राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा द्वारा देश के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण किया गया था। इस पर 114 दिन तक चर्चा हुई तथा 12 अधिवेशन आयोजित किए गए। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत आई थी। भारतीय संविधान में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर, 1946 में स्थाई अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। भारतीय संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। यह 26 नवम्बर 1949 को पूर्ण कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके पश्चात 26 जनवरी, 1950 से देश में संविधान लागू किया गया। इससे पूर्व देश में भारत सरकार अधिनियम-1935 का कानून लागू था। कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं होती है। समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात इसमें 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। ऐसा भविष्य में भी होने की पूर्ण संभावना है। भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य एवं नागरिकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के चार चीफ कमिश्नर थे, जबकि 93 सदस्य देशी रियासतों के थे। विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम सदस्य बने थे। देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ही किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1946 को किया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

भारत एक विशाल देश है। इसमें विभिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। यहां विभिन्न संप्रदायों, पंथों, जातियों आदि के लोग हैं। उनकी, रीति-रिवाज, भाषाएं, रहन-सहन एवं खान-पान भी भिन्न-भिन्न हैं। इस सबके मध्य वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वास्तव में यही भारत का स्वभाव है। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 को मध्य किया गया है। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि पहले संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, जिसे '44वें संविधान संशोधन-1978 के अंतर्गत हटा दिया गया। सातवां मौलिक अधिकार संपति का अधिकार था। मूल अधिकार का एक दृष्टांत है- राज्य नागरिकों के बीच परस्पर विभेद नहीं करेगा।÷ भारतीय संविधान में भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। यही इसकी विशेषता है। भारतीय संविधान हम भारत के लोगों के लिए हमारी अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत जनित स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्श मूल्यों के प्रति एक राष्ट्र के रूप में हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है। वर्तमान के आधुनिक भारत की संकल्पना के समय संविधान निर्माताओं ने इसी सांस्कृतिक विरासत को उसके मूल स्वरूप में अक्षुण्ण रखने के ध्येय से भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के रुचिकर चित्रों को स्थान दिया, जो मूलतः भारतीय संविधान के भारतीय चैतन्य को ही परिभाषित करते हैं। भारतीय ज्ञान परम्परा के अलोक में निर्मित भारतीय संविधान भारत की ऋषि परम्परा का धर्मशास्त्र है। भारतीय जीवन दर्शन का ग्रंथ है।

भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां सबका सम्मान किया जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। यह सनातन धर्म का मूल संस्कार है। यह एक विचारधारा है। महा उपनिषद सहित कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है।

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम् ।।

अर्थात यह मेरा अपना है और यह नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। कहने का अभिप्राय है कि धरती ही परिवार है। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। निसंदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले हैं। वे सबको अपना लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में परस्पर सहयोग भाव बनाए रखते हैं। एक-दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की महानता है। उल्लेखनीय है कि भारत का संविधान बहुत ही परिश्रम से तैयार किया गया है। इसके निर्माण से पूर्व विश्व के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। तत्पश्चात उन पर गंभीर चिंतन किया गया। इन संविधानों में से उपयोगी संविधानों के शब्दों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। आजादी के बाद भारत का वैचारिक दृष्टिकोण भारतीय ज्ञान परम्परा के आलोक में विकास के पाठ पर खड़ा करने का प्रयास होना चाहिए था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत की आत्मा निवास करती है। इसका प्रत्यके शब्द एक मंत्र के समान है। हम भारत के लोग- से अभिप्राय है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है। इसी प्रकार संप्रभुता- से अभिप्राय है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। समाजवादी- से अभिप्राय है कि संपूर्ण साधनों आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य। 'पंथनिरपेक्ष राज्य' शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लोकतांत्रिक- से अभिप्राय है कि लोक का तंत्र अर्थात जनता का शासन। गणतंत्र- से अभिप्राय है कि एक ऐसा शासन जिसमें राज्य का मुखिया एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। न्याय- से आशय है कि सबको न्याय प्राप्त हो। स्वतंत्रता- से अभिप्राय है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता से जीवन यापन करने का अधिकार है। समता- से अभिप्राय है कि देश के सभी नागिरकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रकार बंधुत्व- से अभिप्राय है कि देशवासियों के मध्य भाईचारे की भावना।

विचारणीय विषय यह है कि भारतीय संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए हैं तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। किन्तु देश में आज भी ऊंच-नीच, अस्पृश्यता आदि जैसे बुराइयां व्याप्त हैं। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए कानून भी बनाए गए, परन्तु इनका विशेष लाभ देखने को नहीं मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। सामाजिक समरसता भारतीय समाज की खूबसूरती है, अस्पृश्यता से संबंधित अप्रिय घटनाएं भी चर्चा में रहती हैं। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जागरूक लोगों को आगे आना चाहिए तथा सभी लोगों को अपने देश के संविधान का पालन करना चाहिए।**-एजेंसी**